[2015] 6 एस. सी. आर 638

मद्रास बार संगठन

वी.

भारत संघ और ए. एन. आर.

(2013 की लिखित याचिका (सिविल) संख्या 1072)

14 मई, 2015

[एच. एल. दत्तू, सीजेआई, ए. के. सिकरी, अरुण मिश्रा,

रोहिंटन फाली नरीमन और अमितावा रॉय, जे. जे।]

कंपनी अधिनियम, 2013:

एसएस। 408 , 410 , 421 और 423-राष्ट्रीय संविधान

कंपनी विधि न्यायाधिकरण-एन. सी. एल. टी. और राष्ट्रीय कंपनी विधि

अपीलीय न्यायाधिकरण-एन. सी. एल. ए. टी.-मान्यताः संवैधानिक

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की वैधता बरकरार है-एन. सी. एल. टी. पहली है।

अधिनियम में स्थापित अर्ध-न्यायिक मंचों के पदानुक्रम में मंच,

2013- इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. केवल कानून के सवाल से ही नहीं निपटेगा।

एक दिए गए मामले में जो उसके सामने आ रहा है लेकिन उसे बुलाया जाएगा तथ्यात्मक विवादों/पहलुओं को भी पराजित करना-एन. सी. एल. ए. टी.

एनसीएलटी द्वारा पारित आदेशों की वैधता की जांच करेंगे तथ्यात्मक और कानूनी मुद्दों पर फिर से विचार करें।

एसएस। 409 , 411 - एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष और सदस्य

और एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष और सदस्य -

उनके पद की अवधि और वेतन सहित योग्यताएँ

भत्ते आदि-तकनीकी के संबंध में चुनौती न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य-आयोजितः

एस के अनुसार। 409 (3) (ए) से (ई) और एस। 411 योग्यता निर्धारित करना न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्य की नियुक्ति के लिए और

क्रमशः अपीलीय न्यायाधिकरण, तकनीकी सदस्यों को चाहिए

केवल उन अधिकारियों में से चुना जाए जो पद धारण करते हैं

सचिव या अतिरिक्त सचिव और जिनके पास तकनीकी है

638 मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत संघ 6

विशेषज्ञता-यह आर. गांधी, राष्ट्रपति, मद्रास के खिलाफ है।

बार एसोसिएशन का मामला-इस प्रकार, एस। 409 (3) (ए) और (ई) और एस।

411 (3) अमान्य माना जाता है-तकनीकी नियुक्ति के लिए

एन. सी. एल. टी. के सदस्य, आर. गांधी में निहित निर्देश,

अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन का मामला ईमानदारी से होगा

पालन किया गया और इन सुधारों को एस में किया जाना है। 409 (3) इसे ठीक करने के लिए।

एस. 412 - एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. सदस्यों का चयन -

चयन समिति की संरचना यू/एस। 412- रचना

आर के अनुसार प्रावधान लाकर दोष को दूर करें। गाँधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन का मामला जिसमें यह

चार सदस्यीय समिति होनी चाहिए-दो प्रशासनिक से

शाखा/नौकरशाही और दो न्यायपालिका से।

रिट याचिका का निपटारा करते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 एनसीएलएटी के संविधान का निर्माण

आर. गांधी, राष्ट्रपति, मद्रास में विशेष रूप से बरकरार रखा गया था।

बार एसोसिएशन का मामला-2010 का निर्णय। यह नहीं हो सकता।

इस बात से इनकार किया कि तत्काल याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से

एन. सी. एल. ए. टी. की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाया

इससे पहले रिट याचिका दायर की गई थी और यहां तक कि तर्क भी दिए गए थे

इसी मुद्दे पर। संबंधित प्रावधान

अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन अर्थात धारा 10 एफआर

कंपनी अधिनियम, 1956 पर विधिवत ध्यान दिया गया। एन. सी. एल. टी. के प्रतिष्ठानों को भी चुनौती दी गई एन. सी. एल. ए. टी. के रूप में इस आधार पर कि संसद ने

शक्तियों को छीनकर न्यायाधिकरण का सहारा लिया

सामान्य अदालतों से जो अनिवार्य रूप से एक न्यायिक अदालत थी

कार्य और विधानमंडल का यह कदम प्रभावित करता है

निष्पक्षता, निष्पक्षता और तर्कसंगतता निर्णय लेना जो न्यायपालिका और सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की पहचान थी

[2015

] 6 एस सी आर।

अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य; और यह कि

कानून के शासन को नकारना और सिद्धांत को कुचलना

शक्तियों के पृथक्करण की जो मूल विशेषता थी

भारत का संविधान। याचिकाओं ने नेतृत्व किया

एनसीएलटी दोनों की संवैधानिक वैधता पर भी हमला

इन सामान्य आधारों पर NCLAT के रूप में। अदालत ने विशेष रूप से उन सभी तर्कों के सरगम में गया

और दृढ़ता से उसी को पीछे हटा दिया। न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि न्यायिक कार्य का स्थानांतरण, पारंपरिक रूप से न्यायालयों द्वारा न्यायाधिकरणों के लिए निष्पादित किया जाता है

संविधान की मूल संरचना को आहत किया। [पैरा

11 , 12] [662 - जी-एच; 663-ए-ई]

1.2 संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से निपटा

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की संवैधानिक वैधता

कैप्शन "क्या NCLT और NCLAT का गठन

कंपनी अधिनियम के भाग 1 बी और 1 सी के तहत मान्य हैं। द.

न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की

जिसका मानना था कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का निर्माण नहीं किया गया था

असंवैधानिक है। इसे देखते हुए, यह खुला नहीं है

याचिकाकर्ता इस मुद्दे पर बहस करने के लिए भी क्योंकि यह स्पष्ट रूप से काम करता है

न्यायपालिका के रूप में। एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना को चुनौती दी गई

इस आधार पर कि जहाँ तक इस अपीलीय मंच का संबंध है

संबंधित, उक्त में कोई कारण नहीं दिए गए हैं

निर्णय और उसके बाद इस पहलू पर विचार किया गया

एन. टी. टी. निर्णय में अधिक विवरण जिसमें

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण को असंवैधानिक ठहराया गया था। याचिकाकर्ता का यह दुस्साहस पूरी तरह से है

निराधार है। पहली बार में, एन. सी. एल. ए. टी. की वैधता

फिर से खोला गया। 2010 के मामले में फैसला संविधान का है। न्यायपीठ और एक समन्वित न्यायपीठ का वह निर्णय बाध्य करता है

यह बेंच भी। [पैरा 13,14] [665-ए-जी]

1.3 मद्रास बार एसोसिएशन v में संविधान पीठ के फैसले को पढ़ना।

यूनियन ऑफ इंडिया ई

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण का मामला यह प्रकट करेगा कि

न केवल 2010 के फैसले पर ध्यान दिया गया था, बल्कि

उनका अनुसरण भी किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि

एक ओर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. और दूसरी ओर एन. टी. टी. के बीच की विशेषताएं

दूसरी ओर एक अलग निष्कर्ष पर पहुंचने में। [पैरा 15] [665 - जी-एच; 666-ए]

1.4 एन. टी. टी. एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायिक शक्ति थी।

निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा अब तक की गई समीक्षा

कानून के शुद्ध महत्वपूर्ण प्रश्न की मांग की गई थी

एन. टी. टी. में निहित होने के लिए ले जाया गया जिसे माना गया था

अस्वीकार्य। तत्काल मामले में, ऐसा कोई नहीं है

स्थिति। इसके विपरीत, एन. सी. एल. टी. पहला मंच है

कंपनियों में स्थापित अर्ध-न्यायिक मंचों का पदानुक्रम

अधिनियम, 2013। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. केवल इन मामलों से ही नहीं निपटेगा उसके समक्ष आने वाले किसी मामले में कानून का प्रश्न लेकिन

तथ्यात्मक विवादों/पहलुओं को दूर करने के लिए कहा जाए

साथ ही। एन. सी. एल. ए. टी. जो प्रदान किया गया पहला अपीलीय मंच है

आदेशों की वैधता की जांच करने के लिए अधिनियम, 2013 के तहत एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित, तथ्यात्मक पर भी पुनर्विचार करना होगा

अपीलीय न्यायाधिकरण की अधिकारिता में उल्लेख किया गया है धारा 410 स्वयं जो यह निर्धारित करती है कि एन. सी. एल. ए. टी.

के आदेशों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई के लिए गठित

न्यायाधिकरण '। यह अधिकार क्षेत्र इसके द्वारा सीमित नहीं है

किसी भी प्रकृति की सीमाएँ जो भी हों और

इसका निहितार्थ यह है कि अपील दोनों पर होगी

तथ्यों के साथ-साथ कानून के प्रश्न। इसी तरह,

धारा 421 की उप-धारा (4) के तहत, जो प्रावधान है

'न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील' से संबंधित है, यह प्रदान किया गया है

कि एन. सी. एल. ए. टी. उचित अवसर देने के बाद सुना जाए तो उस पर ऐसे आदेश जारी करें जो वह उचित समझे।

अपील किए गए आदेश को बनाना, संशोधित करना या अलग करना

'के खिलाफ। इसके बाद आगे की अपील की जाती है।

[2015] 6 एस. सी. आर. के अधीन उच्चतम न्यायालय को एन. सी. एल. ए. टी. का आदेश।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अधिनियम की धारा 423। अपील का दायरा

उच्चतम न्यायालय केवल 'कानून के सवाल' तक ही सीमित है। इस तरह के आदेश से उत्पन्न '। [पैरा 16] [666-बी-जी]

1.5 इसे प्रदान करना एक सामान्य विशेषता/अभ्यास है।

अपीलीय मंच जहाँ भी कोई अधिनियम पूर्ण हो

न्यायिक उपचार प्रदान करने के लिए संहिता। एक अधिकार प्रदान करना अपीलीय मंच के समक्ष अपील करना एक अच्छी तरह से स्वीकृत है।

मानक जिसे एक स्वस्थ परंपरा के रूप में माना जाता है। इस प्रकार,

इस मुद्दे में कोई योग्यता नहीं है। [पैरा 17,18] [666-एच; 667-ए

बी]

2.1 2010 के फैसले में, संविधान पीठ ने

यह विचार लिया कि चूंकि एन. सी. एल. टी. अब होगा

जो कार्य किया जा रहा है, उसे करना

अन्य, उच्च न्यायालय द्वारा, एन. सी. एल. टी. के तकनीकी सदस्य /

एन. सी. एल. ए. टी. का चयन केवल उन्हीं में से किया जाना चाहिए सचिव या अतिरिक्त पद धारण करने वाले अधिकारी

सचिव और तकनीकी विशेषज्ञता रखने वाले। भाग 1 सी और

1 अधिनियम, 1956 का डी, जैसा कि वे मौजूद थे, अमान्य माना गया था।

संवैधानिकता के बारे में, न्यायालय ने सुधारों की ओर इशारा किया जिन्हें हटाने की आवश्यकता थी

एनामोलीस। [पैरा 20,21] [670-सी, डी; 673-एफ]

2.2 खंड (ग) और (घ) में निहित प्रावधान

उप-धारा (2) और उप-धारा के खंड (ए) और (बी) (3) धारा 10 एफडी जिसके साथ संयुक्त सचिव बनाए गए

पात्र के रूप में कुछ अनुभव, विशेष रूप से घोषित किए गए थे

अमान्य के रूप में। इसके बावजूद, की धारा 409 (3) अधिनियम, 2013 फिर से संयुक्त सचिव बनाता है

संयुक्त सचिव। यह स्पष्ट रूप से डिक्टा के दांतों में है 2010 के फैसले में घोषित किया गया। [पैरा 22] [677-जी-एच; 678

ए] मद्रास बार एसोसिएशन वी। भारत का संघ

€

2.3 जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाताओं ने

यह कहते हुए इस प्रावधान को उचित ठहराने का प्रयास किया कि यह

उपलब्ध अधिकारियों की कमी को देखते हुए बदलाव किया गया था

भारतीय कंपनी कानून में अतिरिक्त सचिव स्तर पर सेवा करते हैं। यह आगे उल्लेख किया गया है कि कार्यात्मक रूप से स्तर

अतिरिक्त सचिव और संयुक्त सचिव समान हैं। इन अधिकारियों को विशिष्ट मुद्दों की जानकारी है।

कम्पनियों के संचालन और कार्यकरण से संबंधित और

कंपनी कानून में उनकी विशेषज्ञता जो अपेक्षित है

एन. सी. एल. टी. को लाभ पहुँचाएँ। इस तरह का स्पष्टीकरण कानूनी नहीं है।

टिकाऊ, 2010 के स्पष्ट जनादेश को ध्यान में रखते हुए

निर्णय। ऐसे पदों के लिए विचार को सीमित करने के लिए

सचिव और अपर सचिव के लिए, न्यायालय के दिमाग में एक बहुत ही सम्मोहक कारक था।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता का क्रमिक क्षरण, जो था

इसे चिंता का विषय माना जाता है। [पैरा 23] [678-बी-ई]

2.4 उक्त स्पष्ट और स्पष्ट को ध्यान में रखते हुए

2010 के फैसले में कहा गया था कि इसके साथ छेड़छाड़ की जाएगी

स्पष्ट रूप से समझौता करने की क्षमता है

मानकों को जो 2010 के निर्णय ने प्राप्त करने की मांग की, नहीं,

इसलिए उत्साह से सुरक्षित करने की कोशिश की। अतः यह माना जाता है कि धारा 409 (3) (ए) और (ई) अमान्य हैं क्योंकि ये प्रावधान अवैध हैं।

एक ही बुराई से पीड़ित हैं। इसी प्रकार, धारा 411 (3)

तकनीकी योग्यता प्रदान करने के लिए शब्दबद्ध

सदस्यों को भी अमान्य माना जाता है। नियुक्ति के लिए

एन. सी. एल. टी. के तकनीकी सदस्य, में निहित निर्देश

2010 के फैसले के पैरा का ईमानदारी से पालन किया जाएगा और इन सुधारों की आवश्यकता है।

धारा 409 (3) में निहित दोषों को ठीक करने के लिए

उसमें। [पैरा 24] [682-एफ-एच; 683-ए]

3.1 चयन के संबंध में प्रावधान

समिति धारा 10 एफएक्स में निहित थी, वैधता

2010 के फैसले में इस पर सवाल उठाया गया था।

उक्त सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015

] 6 एस सी आर।

चयन समिति की संरचना में त्रुटि पाई गई

2010 के फैसले में संविधान पीठ द्वारा। द.

अदालत ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि 5 सदस्यों के बजाय चयन समिति, इसमें 4 सदस्य होने चाहिए

समिति और यहाँ तक कि इस तरह के चयन की संरचना

फैसले में समिति को अनिवार्य किया गया था।

उपरोक्त के बावजूद, इसमें एक विचलन है चयन समिति की संरचना जो निर्धारित की गई है

अधिनियम, 2013 की धारा 412 (2) के तहत। इसका असर रचना इसे पाँच सदस्यों का चयन बनाना है।

समिति जो 2010 में वैध नहीं पाई गई थी

निर्णय। इन पाँच सदस्यों में से तीन हैं -

प्रशासनिक शाखा/नौकरशाही से दो के खिलाफ

न्यायपालिका जिसके परिणामस्वरूप प्रमुख रूप से कहा जाएगा

प्रशासनिक शाखा से संबंधित सदस्य हैं

ऐसी स्थिति जिसे विशेष रूप से हटा दिया गया था। [पैरा 25,

26] [684 - सी-डी; 685-ए-एफ]

3.2 पीठ के दिमाग में मुख्य विचार

यह था कि वह अध्यक्ष है, अर्थात। भारत के मुख्य न्यायाधीश,

निर्णायक मतदान के अधिकार के साथ चयन का मामला। कि निर्णय और प्रदान करने के कारणों का अनुपात है

इस तरह की रचना की तलाश बहुत दूर नहीं है। के सामने

इस मुद्दे पर उपलब्ध सभी व्यापक निर्देश

एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती के रूप में, किसी के लिए कोई गुंजाइश नहीं है

जैसा कि विवादित प्रावधान के माध्यम से प्राप्त करने की मांग की गई है और यह इसके साथ असंगत है

2010 के निर्णय का अनिवार्य आदेश। इसलिए, अधिनियम, 2013 की धारा 412 (2) के प्रावधान मान्य नहीं हैं।

और दोष को दूर करने के लिए निर्देश जारी किया जाता है

यह प्रावधान 2010 के फैसले के पैरा के अनुसार है।

[पैरा 28] [686-ई-जी]

4. मद्रास बार एसोसिएशन v में शायद ही कोई कानूनी ताकत है।

यूनियन ऑफ इंडिया ई

अवमानना के लिए दंडित करने की उस शक्ति को प्रस्तुत करें जैसा कि दिया गया है अधिनियम की धारा 425 के तहत एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी.

स्वस्थ नहीं है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए; और केंद्र सरकार को गठन करने की शक्ति दी गई है पीठों को फिर से अनुमति नहीं है क्योंकि इस तरह की शक्ति होनी चाहिए

अध्यक्ष, एन. सी. एल. टी. या अध्यक्ष, एन. सी. एल. ए. टी. के साथ आराम करें। इसे करना पड़ता है।

ध्यान रखें कि ये प्रावधान एक में निहित हैं

संसद और याचिकाकर्ता द्वारा अधिनियमित कानून यह नहीं बता सका कि ऐसे प्रावधान कैसे हैं

असंवैधानिक है। [पैरा 29] [687-ए-सी]

5. प्रत्यर्थियों ने उल्लेख करते हुए शपथ पत्र दायर किए हैं

जिसमें आज तक उठाए गए कदम शामिल हैं।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना। चूंकि, की कार्यप्रणाली एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. अब तक शुरू नहीं हुए हैं और यह उच्च समय है।

कि ये न्यायाधिकरण अब काम करना शुरू कर दें, एक उम्मीद है कि उत्तरदाता उपचारात्मक उपाय करेंगे

इस निर्णय में निहित निर्देशों के अनुसार

जल्द से जल्द, ताकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. पर्याप्त हो

कर्मचारी नियुक्त करें और निकट भविष्य में काम करना शुरू करें। [पैरा 31,

33] [687 - डी; 688-एफ]

भारत संघ बनाम। आर. गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार

एसोसिएशन 2010 (6) एससीआर 857: (2010) 11 एस. सी. सी. 1-फॉलो किया गया।

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम। भारत संघ (2014) 10 एससीसी

1 - संदर्भित किया गया।

मामला कानून संदर्भ

पीछा किया। पैरा 11,13,14,24,27,28

2010 (6) एससीआर 857

(2014) 10 एससीसी 1

संदर्भित किया गया। पैरा 10

नागरिक मूल न्यायनिर्णयः लिखित याचिका (सिविल) सं।

1072 2013 का

[भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत] सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट [2015] 6 एस. सी. आर.

अरविंद पी. दातार, निखिल नय्यर, धनजय बैजल एन. साई

विनोद, याचिकाकर्ता के लिए।

पी. एस. पटवालिया पिंकी आनंद, ए. एस. जी., के. राधाकृष्ण, बीनू

तमता, ध्रुव तमता, माधवी दीवान, रेखा पांडे, ए. के. श्रीवास्तव, सुषमा सूरी, बी. वी. बलराम दास, कार्तिक सचदेवा,

करण सेठी, प्रबल बागी, ध्रुव शेरोन, अर्चित उपाध्याय,

नताशा विनायक, नैना पचनंदा, रजत सिंह

उत्तरदाता।

न्यायालय का दिनांकित 14.05.2015 निर्णय था

द्वारा वितरित किया गया

ए. के. सिकरी, जे. याचिकाकर्ता द्वारा दायर यह रिट याचिका,

अर्थात्, मद्रास बार एसोसिएशन, पहले की अगली कड़ी है।

कार्यवाही जो द्वारा दिए गए निर्णय में समाप्त हुई

भारत संघ बनाम में इस न्यायालय की संविधान पीठ। आर.

गांधी, अध्यक्ष, मद्रास बार एसोसिएशन 1 (इसके बाद)

'2010 के फैसले' के रूप में संदर्भित)। पहले दौर में

याचिकाकर्ता ने संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण (संक्षेप में 'एन. सी. एल. टी.') का निर्माण।

और राष्ट्रीय कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण (एन. सी. एल. ए. टी.)

संक्षेप में), उससे संबंधित कुछ अन्य प्रावधानों के साथ

जिन्हें विधानमंडल द्वारा भाग 1 ख में शामिल किया गया था और

1 सी कंपनी अधिनियम, 1956 (इसके बाद के रूप में संदर्भित)

' कंपनी (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा अधिनियम, 1956 ')।

2) रिट याचिका, इस ओर से, याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई थी

मद्रास उच्च न्यायालय जो फैसले में समाप्त हुआ

दिनांकित 30.03.2004। उच्च न्यायालय ने कहा कि एन. सी. एल. टी. का निर्माण

और उच्च न्यायालय द्वारा अब तक प्रयोग की जाने वाली शक्तियों को निहित करना

और कंपनी विधि बोर्ड (संक्षेप में 'सी. एल. बी.') उक्त में न्यायाधिकरण असंवैधानिक नहीं था। लेकिन साथ ही,

उच्च न्यायालय ने विभिन्न प्रावधानों में कुछ खामियों की ओर इशारा किया

अधिनियम, 1956 के भाग 1 बी और भाग 1 और विशेष रूप से मद्रास बार एसोसिएशन v.

भारत संघ 6

[ए. के. सिकरी, जे.]

धारा 10 एफडी (3) (एफ) (जी) (एच), 10 एफई, 10 एफएफ, 10 एफएल (2), 10 एफआर (3),

10 एफ. टी. यह घोषणा करते हुए कि वे प्रावधान मौजूद हैं, शक्तियों के पृथक्करण की बुनियादी संवैधानिक योजना को आहत करते हैं, यह

यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जब तक ये प्रावधान उचित रूप से नहीं हैं

एन. सी. एल. ए. टी. उस अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगी जिसका प्रयोग किया जा रहा है उच्च न्यायालय या सीएलबी द्वारा। याचिकाकर्ता ने दुखी महसूस किया

एन. सी. एल. टी. के किन प्रतिष्ठानों के माध्यम से निर्णय का वह हिस्सा

और एन. सी. एल. ए. टी. को संवैधानिक माना गया। दूसरी ओर, भारत संघ ने फैसले के दूसरे भाग से असंतोष महसूस किया

जिसके द्वारा भाग 1 आर और 1 सी में निहित उपरोक्त प्रावधान

अधिनियम, 1956 को विभिन्न कानूनी समस्याओं से पीड़ित माना गया था।

और संवैधानिक दुर्बलताएँ। इस प्रकार, दोनों भारत संघ भी जैसा कि याचिकाकर्ता ने उस फैसले के खिलाफ अपील दायर की

मद्रास उच्च न्यायालय। उन अपीलों का निर्णय किया गया था

संविधान पीठ, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

3) संविधान पीठ ने उक्त फैसले में कहा कि

एन. सी. एल. टी. की संवैधानिक वैधता के रूप में अनुमोदन की मुहर

और एन. सी. एल. ए. टी. संबंधित है। यह भी अभ्यास किया

भाग 1 ख में निहित उपरोक्त प्रावधानों को देखना

और अधिनियम, 1956 का 1 सी और काफी हद तक सहमत

मद्रास उच्च न्यायालय ने इनमें विभिन्न दोष पाए

प्रावधान। इन दोषों को न्यायालय द्वारा पैरा में सूचीबद्ध किया गया था।

120 उस निर्णय का जो निम्नानुसार हैः

" 120. हम सेट करने के लिए आवश्यक सुधारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं

अधिनियम के भाग I-B और I-C में दोषों को ठीक करनाः

(i) केवल न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं पर विचार किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए।

केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या न्यायाधीश जिन्होंने सेवा की है

कम से कम पाँच वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश का पद या

वह व्यक्ति जिसने दस साल तक वकील के रूप में काम किया है, कर सकता है

न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाए।

ऐसे व्यक्ति जिनके पास समूह ए या समकक्ष है

केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद

भारतीय कंपनी विधि सेवा में अनुभव (कानूनी)

शाखा) और भारतीय कानूनी सेवा (ग्रेड-1) नहीं हो सकती है

न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया गया जैसा कि धारा की उप-धारा 2 (ग) और (घ) में दिया गया है।

10 एफ. डी. कंपनी विधि सेवा या भारतीय में विशेषज्ञता

कानूनी सेवा उन्हें तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार करने में सक्षम बनाएगी।

((ii) एन. सी. एल. टी. उच्च न्यायालय के कार्यों को संभालता है। न्यायालय, सदस्यों को जितना संभव हो उतना होना चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति और स्थिति। यह

इसे प्राप्त किया जा सकता है, न कि वेतन और भत्ते देकर

सदस्यों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लेकिन यह सुनिश्चित करके कि

ऐसे व्यक्ति जो पद, अनुभव या योग्यता में लगभग बराबर हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के रूप में नियुक्त किया जाता है सदस्य। इसलिए, केवल वे अधिकारी जो धारण कर रहे हैं

सचिवों या अतिरिक्त सचिवों के पद

न्यायाधिकरण। उप-धारा (2) के खंड (ग) और (घ) और धारा 10 एफडी की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी)

जो 15 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान करता है

समूह ए पद या संयुक्त पद धारण करने वाले व्यक्ति

केंद्रीय या राज्य में सचिव या समकक्ष पद

सरकार, के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य होना

न्यायाधिकरण के सदस्य अमान्य हैं। (iii) एक "तकनीकी सदस्य" एक अनुभव का अनुमान लगाता है।

जिस क्षेत्र से न्यायाधिकरण संबंधित है। के सदस्य भारतीय कंपनी विधि सेवा जिन्होंने इसके साथ काम किया है

संयोग से कुछ पहलू से निपटा जा सकता है कंपनी कानून को "विशेषज्ञ" योग्य मद्रास बार संगठन नहीं माना जा सकता है।

भारत का संघ

एफ.

[ए. के. सिकरी, जे.]

तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना। इसलिए

भारतीय कंपनी विधि सेवा का एक सदस्य जिसने लेखा शाखा या अन्य में अधिकारियों के साथ काम किया

ऐसे विभाग जिनसे संयोग से निपटा जा सकता है

कंपनी कानून के कुछ पहलू पर विचार नहीं किया जा सकता है। तकनीकी के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य 'विशेषज्ञों' के रूप में

सदस्य। अतः उप-धारा के खंड (क) और (ख)

(3) वैध नहीं हैं। (v) उपखंड (च) का पहला भाग

धारा (3) में यह प्रावधान किया गया है कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास विशेष अधिकार हैं 15 वर्षों का ज्ञान या व्यावसायिक अनुभव

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, अर्थशास्त्र, बैंकिंग, उद्योग कर सकते हैं

कंपनी में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति माने जाएँ

तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए कानून

कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अमान्य है।

(v) क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और विशेष क्षमता वाले व्यक्ति।

कम से कम का ज्ञान और व्यावसायिक अनुभव

औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्निर्माण, निवेश और लेखा में पंद्रह वर्ष,

तकनीकी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र सदस्य।

(vi) खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में

(छ) उप-धारा (3) का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

निर्दिष्ट करें।

(vii) केवल खंड (सी), (डी), (ई), (जी), (एच), और इसके बाद के भाग

धारा 10 की उप-धारा (3) में खंड (च)-एफ. डी. और अधिकारी

सचिव या अतिरिक्त रैंक की सिविल सेवाओं की

भारतीय कंपनी विधि सेवा और भारतीय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट में सचिव

कानूनी सेवा पर इन उद्देश्यों के लिए विचार किया जा सकता हैः

न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति। (viii) अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित) के साथ पांच सदस्यीय चयन समिति के बजाय

और वित्त मंत्रालय के दो सचिव और

कंपनी कार्य और मंत्रालय में सचिव

श्रम और कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव धारा 10 एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में, चयन

समिति को मोटे तौर पर निम्नलिखित तर्ज पर होना चाहिएः

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष (एक निर्णायक वोट के साथ);

(ख) उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के-सदस्य;

(ग) वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव कार्य-सदस्य; और

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव -

सदस्य।

सात या पाँच वर्ष की अवधि के लिए पात्रता के अधीन एक और कार्यकाल के लिए नियुक्ति। ऐसा इसलिए है क्योंकि

कम समय में और जब तक सदस्य प्राप्त करते हैं आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता, एक कार्यकाल

खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तीन साल की उक्त अवधि

65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के रूप में माना जाता है उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या

सेवानिवृत्ति के बाद के स्वर्ग के रूप में माना जाए। अगर ये न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से कार्य करना है

उन्हें युवा सदस्यों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए जो मद्रास समाज v.

भारत का संघ

ई.

[ए. के. सिकरी, जे.]

सेवा की एक उचित अवधि हो। (x) धारा 10 एफई के लिए दूसरा परंतुक

राष्ट्रपति और सदस्यों के साथ ग्रहणाधिकार बनाए रखने के लिए

धारण करते समय उनका मूल संवर्ग/मंत्रालय/विभाग

सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए अनुकूल। कोई भी। सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्ति को तैयार रहना चाहिए।

कार्यपालिका से खुद को पूरी तरह से अलग करना। द.

अतः ग्रहणाधिकार एक वर्ष की अवधि से अधिक नहीं हो सकता है।

(xi) सेवा में स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए,

धारा 10 एफजे और धारा 10 एफवी की उप-धारा (3) राष्ट्रपति के निलंबन का प्रावधान करना चाहिए /

न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य केवल हो सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से।

(xii) ए. आई. आई. न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता कानून और न्याय मंत्रालय से होना चाहिए। न ही

न्यायाधिकरण और न ही इसके सदस्य मांगेंगे या प्रदान किए जाएंगे

संबंधित प्रायोजक से सुविधाओं के साथ या मूल मंत्रालय या संबंधित विभाग।

(xiii) न्यायाधिकरण की दो-सदस्य पीठों को हमेशा ऐसा करना चाहिए

एक न्यायिक सदस्य रखें। जब भी कोई बड़ा या

विशेष पीठों का गठन किया जाता है, जिनकी संख्या

तकनीकी सदस्य न्यायिक सीमा से अधिक नहीं होंगे। सदस्यों "।

4) उपरोक्त के आधार पर, आंशिक रूप से अनुमति देते हुए

हालांकि, उन्हें निम्नलिखित शर्तों में निपटाया गया थाः

" 57. इसलिए हम इन अपीलों का आंशिक रूप से निपटारा करते हैं।

उन्हें निम्नानुसार अनुमति दें:

(i) हम उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखते हैं कि राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण और राष्ट्रीय सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट का निर्माण

[2015

] 6 एस सी आर।

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण और उन्हें निहित करते हुए,

उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियाँ और अधिकार क्षेत्र

कंपनी कानून मामलों के संबंध में, नहीं हैं असंवैधानिक है।

((ii) हम घोषणा करते हैं कि अधिनियम के भाग 1 ख और 1 सी इस प्रकार हैं - वर्तमान में संरचित, कारणों से असंवैधानिक हैं

पूर्ववर्ती पैरा में वर्णित है। हालांकि, पार्ट्स आईबी और आईसी

अधिनियम के, बनाने के द्वारा कार्यान्वित किया जा सकता है

केंद्र सरकार जिस पर पहले ही सहमत हो चुकी है, उसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है, उपयुक्त संशोधन उच्च न्यायालय के विवादित आदेश का पालन "।

5) हालांकि फैसला वर्ष 2010 में आया था, जिसे बरकरार रखा गया था

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का निर्माण, ये दोनों निकाय नहीं कर सके

इसके तुरंत बाद बनाया और कार्यात्मक बनाया जाए और

मामला किसी न किसी तरह की उलझन में फंस गया। यह है।

उन कारकों का पता लगाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उनमें से कुछ हैं

रिट याचिका No.267/2012 की विषय वस्तु जो रिट करती है

याचिका भी इसी याचिकाकर्ता द्वारा दायर की गई है और लंबित है। विचार करें। उक्त रिट याचिका इस पीठ के समक्ष सूचीबद्ध की गई थी

वर्तमान रिट याचिका और कुछ तर्कों के साथ

याचिका में भी विस्तार से सुना गया। हालांकि, मुद्दों के बाद से

उक्त याचिका में आगे की प्रतिक्रिया की आवश्यकता है

भारत संघ, पक्षों की सहमति से, यह माना गया था

उस याचिका में सुनवाई को स्थगित करने का अधिकार, की प्रतीक्षा में

प्रतिक्रिया दें। जहाँ तक वर्तमान रिट याचिका का संबंध है,

हालांकि कुछ हद तक रिट याचिका No.267/2012 से जुड़ा हुआ है,

इस रिट याचिका में की गई प्रार्थनाएँ पूरी तरह से अलग हैं और वहाँ

सुनवाई के साथ आगे बढ़ने में कोई बाधा या बाधा नहीं थी

तत्काल रिट याचिका। इस कारण से, तर्क थे

आखिरकार इस मामले में सुनवाई हुई।

6) वर्तमान रिट याचिका को स्वीकार करते हुए, ऐसा हुआ

कि संसद ने इस रूप में नया कंपनी कानून पारित किया है

भारतीय कंपनी अधिनियम, 2013 (इसके बाद मद्रास बार एसोसिएशन के रूप में संदर्भित)

भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.]

' अधिनियम, 2013 ') जो पूर्ववर्ती अधिनियम, 1956 का स्थान लेता है। इस अधिनियम में,

इसके संबंध में फिर से ठोस प्रावधान किए गए हैं -

एन. सी. एल. टी और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना। यह स्पष्ट है कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के गठन से संबंधित प्रावधान एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की संरचना और गठन

नियुक्ति के लिए योग्यताओं से संबंधित प्रावधान अध्यक्ष/अध्यक्ष और सदस्य (न्यायिक और साथ ही

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों के तकनीकी) और संबंधित प्रावधान भी।

चयन समिति के गठन के लिए

उक्त सदस्यों को भी अधिनियम में शामिल किया गया है।

2013. ये धारा 10 एफडी, 10 एफई, 10 एफएफ के अनुरूप हैं।

10 एफ. एल., 10 एफ. आर. और 10 एफ. टी. जो अधिनियम, 1956 में पेश किए गए थे।

कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा। दाखिल करने का कारण

याचिकाकर्ता द्वारा वर्तमान याचिका का आरोप है

याचिकाकर्ता जो 2010 में दिए गए विभिन्न निर्देशों के बावजूद

निर्णय, अधिनियम, 2013 में नए प्रावधान लगभग चालू हैं

वही रेखाएँ जो अधिनियम, 1956 में शामिल की गई थीं और

इसलिए, इन प्रावधानों के दुष्प्रभाव से पीड़ित हैं

असंवैधानिकता के साथ-साथ 2010 में अनुपात के अनुप्रयोग पर

निर्णय। अतः याचिकाकर्ता द्वारा इस बात पर जोर दिया जाता है कि ये

धारा 408,409,411 (3) में निहित प्रावधान,

412 , 413 , 425 , 431 और अधिनियम, 2013 की धारा 434 अधिकार से बाहर हैं।

संविधान के अनुच्छेद 14 के प्रावधान और, इसलिए,

असंवैधानिक के रूप में निरस्त करने का आदेश। सटीक

रिट याचिका में निहित प्रार्थना निम्नानुसार हैः

" (i) एक लिखित आदेश, आदेश या निर्देश विशेष रूप से

घोषणा के लेखन की प्रकृति यह घोषणा करती है कि

कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXVII के प्रावधान, अधिक

विशेष रूप से धारा 408,409,411 (3), 412,413,425,431 और

434 अधिनियम के अनुच्छेद 14 के प्रावधानों के अधिकार से बाहर

संविधान और तदनुसार उक्त प्रावधानों को निरस्त करना असंवैधानिक के रूप में;

((ii) कोई भी आदेश या ऐसा आगे का आदेश या आदेश पारित करें जो सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के अधीन हो।

[2015

] 6 एस सी आर।

के तथ्यों और परिस्थितियों में उपयुक्त और उचित समझा जाए

वर्तमान मामला "।

7) इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, हम तय करना चाहेंगे

अधिनियम, 2013 के उपरोक्त प्रावधान धारा के साथ

2 (4) , धारा 2 (90) और धारा 407 जिसमें कुछ प्रावधान थे - उठाये गए विवाद के संदर्भ में प्रासंगिक परिभाषाएँ

वर्तमान याचिका में:

" 2 (4) " अपीलीय न्यायाधिकरण "का अर्थ है राष्ट्रीय कंपनी धारा 410 के तहत गठित विधि अपीलीय न्यायाधिकरण;

" 2 (90) " न्यायाधिकरण "का अर्थ है राष्ट्रीय कंपनी कानून।

धारा 408 के तहत गठित न्यायाधिकरण;

407. इस अध्याय में, जब तक कि संदर्भ अन्यथा न हो।

आवश्यकता है,

((क) "अध्यक्ष" से अभिप्रेत है -

अपीलीय न्यायाधिकरण;

((ख) "न्यायिक सदस्य" से न्यायाधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।

या इस प्रकार नियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण और इसमें शामिल हैं

अध्यक्ष या अध्यक्ष, जैसा भी मामला हो;

((ग) "सदस्य" से कोई सदस्य अभिप्रेत है, चाहे वह न्यायिक हो या न्यायिक।

न्यायाधिकरण या अपीलीय न्यायाधिकरण का तकनीकी और

अध्यक्ष या अध्यक्ष को शामिल करता है, जैसा कि मामला है

हो सकता है;

((घ) "अध्यक्ष" से न्यायाधिकरण का अध्यक्ष अभिप्रेत है; (ङ) "तकनीकी सदस्य" से न्यायाधिकरण का सदस्य अभिप्रेत है।

या इस प्रकार नियुक्त अपीलीय न्यायाधिकरण।

408. राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण का गठन

केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, मद्रास समाज बनाम का गठन करेगी।

भारत संघ €

[ए. के. सिकरी, जे.]

ऐसी तारीख से प्रभावी, जो उसमें निर्दिष्ट की जाए,

न्यायाधिकरण को राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के रूप में जाना जाएगा

एक राष्ट्रपति और इतनी संख्या में न्यायिक और तकनीकी सदस्य, जैसा कि केंद्र सरकार मान सकती है

आवश्यक, अधिसूचना द्वारा इसके द्वारा नियुक्त किया जाना, अभ्यास करने के लिए और ऐसी शक्तियों और कार्यों का निर्वहन करें जो हैं, या हो सकते हैं -

उस समय के लिए इस अधिनियम या किसी अन्य कानून द्वारा या उसके तहत प्रदान किया गया

बल में होना।

409. अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता

न्यायाधिकरण

पाँच साल के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। (2) एक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा

न्यायिक सदस्य जब तक कि वह ((क) उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है; या

(ख) कम से कम पाँच वर्षों से जिला न्यायाधीश है या रहा है;

या

(ग) कम से कम दस साल तक किसी अदालत का वकील रहा हो।

स्पष्टीकरण। खंड (ग) के प्रयोजनों के लिए, उस अवधि की गणना करना जिसके दौरान किसी व्यक्ति ने

जिसके दौरान व्यक्ति ने न्यायिक पद संभाला है या किसी न्यायाधिकरण के सदस्य का पद या उसके अधीन कोई पद

संघ या राज्य, जिसके बाद कानून के विशेष ज्ञान की आवश्यकता होती है

वह एक वकील बन जाता है।

(3) एक व्यक्ति के रूप में नियुक्ति के लिए योग्य नहीं होगा

तकनीकी सदस्य जब तक कि वह -

(ए) कम से कम पंद्रह वर्षों से सदस्य रहा है भारतीय निगमित विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

जिनमें से कम से कम तीन वर्ष वेतनमान में होंगे।

भारत सरकार के संयुक्त सचिव या समकक्ष

उस सेवा में या उससे ऊपर; या

(ग) कम से कम पंद्रह वर्षों से लागत लेखाकार के रूप में व्यवहार में है या रहा है; या (घ) कंपनी सचिव के रूप में व्यवहार में है या रहा है।

कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए; या (ई) सिद्ध क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है।

विशेष ज्ञान और अनुभव होना, कम नहीं

पंद्रह साल से अधिक, कानून, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक में

प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक पुनर्निर्माण,

निवेश, लेखांकन, श्रम मामले या ऐसे अन्य मामले।

प्रबंधन, मामलों के संचालन से संबंधित विषय,

कंपनियों का पुनरुद्धार, पुनर्वास और समापन; या

(च) कम से कम पाँच वर्षों से अध्यक्ष है या रहा है।

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का अधिकारी औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत गठित।

410. अपीलीय न्यायाधिकरण का गठन केंद्र सरकार, अधिसूचना द्वारा, निम्नलिखित का गठन करेगी -

उस तारीख से प्रभावी जो उसमें निर्दिष्ट की जाए,

कंपनी विधि अपीलीय न्यायाधिकरण जिसमें एक अध्यक्ष और इतनी संख्या में न्यायिक और तकनीकी

केंद्रीय के रूप में सदस्य, ग्यारह से अधिक नहीं

सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना उचित समझा जा सकता है

अधिसूचना, के आदेश के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए

न्यायाधिकरण।

411. मद्रास बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता।

भारत संघ

[ए. के. सिकरी, जे.]

अपीलीय न्यायाधिकरण

(1) अध्यक्ष एक ऐसा व्यक्ति होगा जो है या रहा है।

उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश या किसी न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय।

(2) न्यायिक सदस्य एक ऐसा व्यक्ति होगा जो है या है।

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो या पाँच साल तक न्यायाधिकरण का न्यायिक सदस्य रहा हो।

(3) एक तकनीकी सदस्य सिद्ध क्षमता वाला व्यक्ति होगा,

सत्यनिष्ठा और विशेष ज्ञान रखने वाली स्थिति और

कानून में कम से कम बीस-पाँच वर्ष का अनुभव,

औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या

लेखांकन, श्रम मामले या ऐसे अन्य विषय प्रबंधन, कार्य संचालन, पुनरुद्धार से संबंधित,

कंपनियों का पुनर्वास और समापन।

412. न्यायाधिकरण के सदस्यों का चयन और

अपीलीय न्यायाधिकरण

(1) न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और अध्यक्ष और

अपीलीय न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य होंगे -

भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद नियुक्त।

(2) न्यायाधिकरण के सदस्य और तकनीकी

अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्यों की नियुक्ति की जाएगी।

चयन समिति की सिफारिश पर

जिसमें शामिल हैं

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष;

(ख) उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश-सदस्य;

(ग) निगमित कार्य मंत्रालय में सचिव

सदस्य; [2015] 6

एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

((घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

सदस्य; और

(ई) वित्तीय सेवा विभाग में सचिव

वित्त मंत्रालय-सदस्य।

(3) निगमित कार्य मंत्रालय के सचिव होंगे

चयन समिति के संयोजक।

(4) चयन समिति इसका निर्धारण करेगी

उप-धारा के तहत व्यक्तियों की सिफारिश करने की प्रक्रिया

(2) .

(5) न्यायाधिकरण के सदस्यों की कोई नियुक्ति नहीं या

अपीलीय न्यायाधिकरण केवल किसी रिक्ति या संविधान के गठन में किसी दोष के कारण अमान्य होगा।

चयन समिति।

413. अध्यक्ष, अध्यक्ष और अध्यक्ष का कार्यकाल

(1) राष्ट्रपति और न्यायाधिकरण का प्रत्येक अन्य सदस्य से पाँच साल की अवधि के लिए इस तरह का पद धारण करेगा

जिस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, लेकिन

पाँच वर्ष के अन्य कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र।

(2) न्यायाधिकरण का एक सदस्य इस प्रकार का पद धारण करेगा जब तक वह प्राप्त नहीं करता,

(क) राष्ट्रपति के मामले में, साठ-सात वर्ष की आयु वर्षों से;

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, साठ-पाँच वर्ष की आयु वर्षः

बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष पूरे नहीं किए हैं

आयु का व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः

बशर्ते कि सदस्य मद्रास समाज V के साथ अपना ग्रहणाधिकार बनाए रख सके।

भारत संघ

ई.

[ए. के. सिकरी, जे.]

जैसा भी मामला हो, उसका मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग हो सकता है, एक अवधि के लिए इस तरह के पद धारण करते हुए नहीं

एक वर्ष से अधिक।

(3) अपीलीय न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य से पाँच साल की अवधि के लिए इस तरह का पद धारण करेगा

जिस तारीख को वह अपने पद पर प्रवेश करेगा, लेकिन

पाँच वर्ष के अन्य कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्ति के लिए पात्र। (4) अपीलीय न्यायाधिकरण का एक सदस्य पद धारण करेगा।

जब तक वह प्राप्त नहीं करता,

(क) अध्यक्ष के मामले में सत्तर वर्ष की आयु

वर्षों से;

(ख) किसी अन्य सदस्य के मामले में, साठ वर्ष की आयु सात वर्षः

बशर्ते कि एक व्यक्ति जिसने पचास वर्ष पूरे नहीं किए हैं

आयु वर्ग सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगाः बशर्ते कि सदस्य अपने ग्रहणाधिकार को बनाए रख सके

जैसा भी मामला हो, उसका मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग हो सकता है, एक अवधि के लिए इस तरह के पद धारण करते हुए नहीं

एक वर्ष से अधिक।

414. वेतन, भत्ते और अन्य शर्तें और

वेतन, भत्ते और अन्य नियम और शर्तें न्यायाधिकरण के सदस्यों की सेवा और

अपीलीय न्यायाधिकरण ऐसा होगा जो निर्धारित किया जाएः बशर्ते कि न तो वेतन और भत्ते और न ही

सदस्यों की सेवा के अन्य नियम और शर्तें

उनके बाद उनके नुकसान के लिए भिन्न होगा

नियुक्ति।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015] 6 एस सी आर।

425. अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति

न्यायाधिकरण और अपीलीय न्यायाधिकरण के पास होगा

के संबंध में समान अधिकार क्षेत्र, शक्तियाँ और प्राधिकरण

स्वयं की अवमानना जैसा कि उच्च न्यायालय ने किया है और हो सकता है

प्रयोग, इस उद्देश्य के लिए, के तहत शक्तियों

न्यायालय अवमानना अधिनियम, 1971 के प्रावधान, जो

परिवर्तनों के अधीन प्रभाव होगा कि

(क) उसमें उच्च न्यायालय को निर्देश होगा - न्यायाधिकरण के लिए एक संदर्भ को शामिल करने के रूप में समझा गया और

अपीलीय न्यायाधिकरण; और (ख) महाधिवक्ता का संदर्भ। की धारा 15

उक्त अधिनियम का अर्थ ऐसे विधि अधिकारियों के प्रति निर्देश के रूप में किया जाएगा जिन्हें केंद्र सरकार निर्दिष्ट करे। इस ओर से "।

8) प्रार्थना खंड में, धाराओं की संवैधानिक वैधता

415 , 418 , 424 , 426 , 431 और 434 से भी पूछताछ की गई है।

सुनवाई के समय, श्री द्वारा कोई तर्क संबोधित नहीं किया गया था।

दातार, उपरोक्त पर याचिकाकर्ता के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील

प्रावधान। इसलिए, इन प्रावधानों के संबंध में, हम अपनी चर्चा को छोड़ रहे हैं।

9) उपरोक्त प्रावधानों को पढ़ने पर और

बार में दिए गए तर्कों के संबंध में, हम कर सकते हैं

आसानी से चुनौती को तीन खंडों में वर्गीकृत करें,

निम्नानुसारः

(i) एन. सी. टी. के संविधान की वैधता को चुनौती और

NCLAT;

((ii) योग्यताओं के प्रिस्क्रिप्शन के लिए चुनौती

एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष और सदस्य और साथ ही अध्यक्ष और एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्य; मद्रास समाज v.

भारत का संघ

ई.

[ए. के. सिकरी, जे.]

((ग) चयन समिति की संरचना को चुनौती

एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष/सदस्यों की नियुक्ति के लिए और

एनसीएलएटी के अध्यक्ष/सदस्य।

इन्हें दी गई शक्तियों से संबंधित आकस्मिक मुद्दे

धारा 425 में उल्लिखित अवमानना के लिए दंड देने वाले निकाय और केंद्र सरकार को गठन करने की शक्ति देना

याचिकाकर्ता द्वारा पीठ भी खड़ी की जाती है।

जैसा कि आगे चर्चा की जाएगी, ये सभी मुद्दे खड़े हैं।

मद्रास बार एसोसिएशन (ऊपर) द्वारा कवर किया गया और इसका जवाब

ये प्रश्न वहाँ उपलब्ध हैं। वास्तव में, विस्तृत जानकारी के बाद

प्रत्येक मुद्दे पर चर्चा करते हुए न्यायालय ने फैसला सुनाया।

इसलिए, विभिन्न प्रकार की समस्याओं का निदान करते समय

उठाया, हम उपचार का प्रबंधन करेंगे जो है

उस निर्णय में निर्धारित।

इश्यू नंबर 1

री. : एन. सी. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की संवैधानिक वैधता

अधिनियम, 2013 की धारा 408 के संविधान से संबंधित है

एनसीएलटी। इस धारा के आधार पर, केंद्र सरकार है

न्यायाधिकरण के गठन के लिए अधिसूचना जारी करने का अधिकार

'राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण' के रूप में जाना जाएगा। यह न्यायाधिकरण

राष्ट्रपति और इतनी संख्या में न्यायिक और

तकनीकी सदस्य, जैसा कि केंद्र सरकार मान सकती है

इसके द्वारा नियुक्त किया जाना आवश्यक है। दिनांकित अधिसूचना द्वारा

12.09.2013 , केंद्र सरकार ने एन. सी. एल. टी. का गठन किया है।

इसी तरह, अधिनियम, 2013 की धारा 410 केंद्र को हथियार देती है।

अधिसूचना द्वारा एन. सी. एल. ए. टी. का गठन करने की शक्ति वाली सरकार। इस एन. सी. एल. ए. टी. में एक अध्यक्ष और ऐसी संख्या भी शामिल होगी।

न्यायिक और तकनीकी सदस्यों की, जो ग्यारह से अधिक न हों,

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाना उचित समझा जा सकता है

अधिसूचना। उपरोक्त अधिसूचना दिनांक 12.09.2013 के अनुसार,

एन. सी. एल. ए. टी. का गठन भी केंद्र सरकार द्वारा किया गया है।

10) यह इंगित करना उचित है कि प्रार्थना खंड में, हालांकि धारा 408 के अधिकारों को चुनौती दी गई है, यह

राहत के रूप में एन. सी. एल. ए. टी. के गठन को कोई चुनौती नहीं है। दावा किया गया है। इसके अलावा, जैसा कि ऊपर बताया गया है,

पूरी रिट याचिका संविधान पीठ के तहत नाराज़गी उठाती है

2010 के फैसले में फैसला। हालाँकि, बहस के समय,

श्री दातार ने मुख्य रूप से संवैधानिक वैधता को चुनौती दी

एन. सी. एल. ए. टी. ने चुनौती देने के लिए कोई गंभीर प्रयास किए बिना

एन. सी. एल. टी. का गठन। जहाँ तक एन. सी. एल. टी. का संबंध है, वह लगभग यह स्वीकार किया कि 2010 के फैसले में इसकी वैधता बरकरार है

और बहस करने के लिए बहुत कुछ नहीं है। एन. सी. एल. ए. टी. के संबंध में, हालांकि

उन्होंने स्वीकार किया कि उपरोक्त निर्णय में इसकी वैधता को भी बरकरार रखा गया है, उनका प्रयास यह प्रदर्शित करना था कि कोई नहीं है

जहाँ तक एन. सी. एल. ए. टी. का संबंध है, पूरे निर्णय में चर्चा

संबंधित और इसलिए, निष्कर्ष जिसका उल्लेख किया गया है

अंत में उक्त निर्णय को बाध्यकारी नहीं माना जाना चाहिए

या इस मुद्दे का निर्णय लेने के रूप में लिया जाना चाहिए। उनका समर्पण

यह था कि बाद के संविधान पीठ के फैसले को देखते हुए

मद्रास बार एसोसिएशन बनाम में इस न्यायालय का। भारत संघ 2,

जिसमें राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण की स्थापना की गई है।

असंवैधानिक होने के लिए, धारा 410 को भी लागू किया जाना चाहिए

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण से संबंधित उक्त निर्णय में दर्ज कारणों के लिए समान व्यवहार। यह मुश्किल है

विभिन्न कारणों से इस तर्क को पचाना, जिसे हम दर्ज करते हैं इसके बाद की चर्चा।

11) सबसे पहले एन. सी. एल. ए. टी. का संविधान बनाया गया है

2010 के फैसले में विशेष रूप से बरकरार रखा गया था। इससे इनकार नहीं किया जा सकता।

कि इसी याचिकाकर्ता ने विशेष रूप से सवाल किया था

यहाँ तक कि इसी मुद्दे पर तर्क भी दिए। यह तथ्य है कि उक्त निर्णय में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है। प्रावधान

अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन से संबंधित अर्थात

निगम अधिनियम, 1956 की धारा 10 एफआर को विधिवत रूप से लिया गया था।

मद्रास बार एसोसिएशन V. भारत संघ €

[ए. के. सिकरी, जे.]

नोट करें। एन. सी. एल. टी. के प्रतिष्ठानों को चुनौती दी गई थी

साथ ही एन. सी. एल. ए. टी. इस आधार पर कि संसद ने सहारा लिया था

सामान्य से शक्तियाँ छीनकर न्यायाधिकरण बनाने के लिए

न्यायालय जो अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य था और यह कदम

विधायिका की निष्पक्षता, निष्पक्षता और निर्णय लेने की तर्कसंगतता जो पहचान थी

न्यायपालिका और अनिवार्य रूप से एक न्यायिक कार्य। तर्क चला गया

इस हद तक कि यह कानून के शासन को नकारने के बराबर है और

शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कुचलना जो था भारत के संविधान की मूल विशेषता। हम क्या हैं?

इस बात पर जोर देते हुए कि याचिकाओं ने हमले का नेतृत्व किया

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. दोनों की संवैधानिक वैधता

ये सामान्य आधार हैं। न्यायालय ने विशेष रूप से

उन सभी तर्कों का सरगम उठाया गया और दृढ़ता से खारिज कर दिया गया

एक ही।

12) न्यायालय ने विशेष रूप से इस तर्क को खारिज कर दिया कि

न्यायिक कार्य का हस्तांतरण, पारंपरिक रूप से द्वारा निष्पादित

संविधान और इस संबंध में स्थिति को संक्षेप में प्रस्तुत किया इसके अंतर्गतः

" हम स्थिति को संक्षेप में इस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं:

(ए) एक विधायिका एक कानून बना सकती है जिसे स्थानांतरित किया जा सकता है

किसी विनिर्दिष्ट के संबंध में न्यायालयों द्वारा प्रयोग की जाने वाली अधिकारिता

विषय (उन लोगों के अलावा जो न्यायालयों में निहित हैं) संविधान के प्रावधानों को व्यक्त करना) किसी भी न्यायाधिकरण को।

((ख) सभी न्यायालय न्यायाधिकरण हैं। कोई भी न्यायाधिकरण जिसके लिए न्यायालयों के किसी भी मौजूदा अधिकार क्षेत्र को स्थानांतरित किया जाना चाहिए

न्यायिक न्यायाधिकरण भी हो। इसका अर्थ है कि ऐसा न्यायाधिकरण

सदस्यों के रूप में, किसी पद के व्यक्ति होने चाहिए,

क्षमता और स्थिति जितना संभव हो उतना बराबर

न्यायालय के पद, स्थिति और क्षमता के लिए जो

तब तक ऐसे मामलों से निपट रहे थे और सदस्य सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट प्रस्तुत करते थे

न्यायाधिकरण की स्वतंत्रता होनी चाहिए और न्यायिक न्यायाधिकरणों से जुड़े कार्यकाल की प्रतिभूति।

(ग) जब भी 'न्यायाधिकरणों' की आवश्यकता होती है, कोई नहीं होता है।

यह धारणा कि इसमें तकनीकी सदस्य होने चाहिए

न्यायाधिकरणों। जब कोई अधिकार क्षेत्र न्यायालयों से स्थानांतरित किया जाता है न्यायाधिकरणों को, विचाराधीनता और देरी के आधार पर

अदालतें, और इस प्रकार हस्तांतरित अधिकार क्षेत्र नहीं है

सहायता की आवश्यकता वाले किसी भी तकनीकी पहलू को शामिल करें विशेषज्ञों की, न्यायाधिकरणों को आम तौर पर केवल होना चाहिए

न्यायिक सदस्य। केवल जहाँ अधिकारिता का प्रयोग हो

तकनीकी या विशेष में जांच और निर्णय शामिल हैं

पहलू, जहाँ तकनीकी सदस्यों की उपस्थिति होगी उपयोगी और आवश्यक, न्यायाधिकरणों के पास तकनीकी होना चाहिए

सदस्य। तकनीकी की अविवेकी नियुक्ति

सभी न्यायाधिकरणों के सदस्य कमजोर होंगे और प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता।

(घ) विधायिका निम्नलिखित अधिकारिताओं को फिर से व्यवस्थित कर सकती है -

उच्च न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने वाले मामलों की निर्दिष्ट श्रेणी कर सकती है निचली अदालत द्वारा या इसके विपरीत मुकदमा चलाया जाए (एक मानक)

उदाहरण न्यायालयों की आर्थिक सीमाओं की भिन्नता है)।

इसी तरह न्यायाधिकरणों का गठन करते समय, विधानमंडल कर सकता है

योग्यता/पात्रता मानदंड निर्धारित करें। वैसा ही। हालाँकि यह न्यायिक समीक्षा के अधीन है। अगर अदालत में

न्यायिक पुनर्विलोकन के अभ्यास का विचार है कि

न्यायाधिकरण से स्वतंत्रता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा

न्यायपालिका या न्यायपालिका के मानकों, न्यायालय कर सकता है

शक्तियाँ और किसी भी अतिक्रमण को रोकने के लिए, जानबूझकर या अनजाने में, या तो विधायिका द्वारा या द्वारा

कार्यकारी "। मद्रास बार एसोसिएशन v. भारत का संघ

[ए. के. सिकरी, जे.]

13) इसके बाद, संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से विचार किया

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की संवैधानिक वैधता के साथ

शीर्षक "क्या एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का गठन

कंपनी अधिनियम के भाग 1 बी और 1 सी वैध हैं ", और शुरू किए गए हैं। इस विषय पर विस्तृत चर्चा। यह प्रकट हो जाता है।

उपरोक्त से कि एन. सी. एल. ए. टी. की वैधता का प्रश्न था

सीधे और स्पष्ट रूप से मुद्दे में। चुनौती के विभिन्न पहलू

इन दोनों मंचों की वैधता को पूरी तरह से कुचल दिया गया था

बाहर निकलें। निस्संदेह, अधिकांश चर्चा पैरा 107 में निहित है।

119 एन. सी. एल. टी. को संदर्भित करता है। हालांकि, उक्त में एक अंतर्दृष्टि पर

इन अनुच्छेदों में निहित चर्चा, वाक्पटुता से

यह ध्यान रखें कि इसमें एन. सी. एल. ए. टी. भी शामिल है। के पैरा 121 में

निर्णय, जो पहले से ही ऊपर निकाला गया है, न्यायालय ने विशेष रूप से उच्च न्यायालय के निर्णय की पुष्टि की जिसमें कहा गया था

कि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. का निर्माण असंवैधानिक नहीं था। में।

इसे देखते हुए, यह याचिकाकर्ता के लिए यह तर्क देने के लिए भी खुला नहीं है

यह स्पष्ट रूप से रेस जुडिकाटा के रूप में कार्य करता है।

14) सच कहें तो श्री दातार उपरोक्त बातों से अवगत थे।

सीमा। फिर भी उन्होंने एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना पर हमला करने का साहस किया।

इस आधार पर कि जहाँ तक इस अपीलीय मंच का संबंध है,

उक्त निर्णय में और उसके बाद कोई कारण नहीं दिए गए हैं।

एनटीटी में इस पहलू पर अधिक विस्तार से चर्चा की गई है।

फैसला जिसमें राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण का गठन किया गया है

असंवैधानिक माना जाता है। याचिकाकर्ता का यह दुस्साहस पूरी तरह से निराधार है। पहली बार में, जैसा कि उल्लेख किया गया है

ऊपर, जहां तक एन. सी. एल. ए. टी. का संबंध है, इसकी वैधता पहले से ही है।

इसे बरकरार रखा गया और इस मुद्दे को फिर से नहीं खोला जा सकता है। निर्णय में

2010 के फैसले का मामला एक संविधान पीठ का है और वह एक समन्वित पीठ का निर्णय इस पीठ को भी बाध्य करता है।

15) दूसरा, संविधान पीठ के फैसले को पढ़ना।

राष्ट्रीय कर न्यायाधिकरण के मामले में यह स्पष्ट होगा कि नहीं केवल 2010 के फैसले पर ध्यान दिया गया था लेकिन उसका पालन भी किया गया था।

न्यायालय ने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों के बीच की विशिष्ट विशेषताओं को स्पष्ट किया

[2015

] 6 एस सी आर।

एक ओर एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. और दूसरी ओर एन. टी. टी

एक अलग निष्कर्ष पर पहुँचें।

16) तीसरा, एन. टी. टी. एक ऐसा मामला था जिसमें न्यायपालिका की शक्ति थी।

निर्णय लेने में उच्च न्यायालय द्वारा अब तक की गई समीक्षा

कानून के शुद्ध महत्वपूर्ण प्रश्न को एन. टी. टी. में निहित करने के लिए दूर करने की मांग की गई थी जिसे अस्वीकार्य माना गया था। में। तत्काल मामले में, ऐसी कोई स्थिति नहीं है। इसके विपरीत,

एन. सी. एल. टी. अर्ध-न्यायिक मंचों के पदानुक्रम में पहला मंच है

अधिनियम, 2013 में स्थापित। इस प्रकार, एन. सी. एल. टी. केवल सौदा ही नहीं करेगा

किसी दिए गए मामले में कानून का सवाल उसके सामने आता है लेकिन

तथ्यात्मक विवादों/पहलुओं को समाप्त करने के लिए कहा जाए

ठीक है। इस परिदृश्य में, एन. सी. एल. ए. टी. पहला अपीलीय मंच है

एन. सी. एल. टी. द्वारा पारित आदेशों को तथ्यात्मक पर भी पुनर्विचार करना होगा कानूनी मुद्दों के रूप में। इसलिए, स्थिति एन. टी. टी. के समान नहीं है।

अपीलीय न्यायाधिकरण की अधिकारिता का उल्लेख धारा में किया गया है।

410 स्वयं जो यह निर्धारित करता है कि एन. सी. एल. ए. टी. का गठन 'न्यायाधिकरण के आदेशों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई के लिए' किया जाएगा। यह

अधिकार क्षेत्र किसी भी प्रकृति की सीमाओं से सीमित नहीं है। जो भी हो और इसका निहितार्थ यह है कि अपील

तथ्यों के साथ-साथ कानून के प्रश्नों दोनों पर झूठ बोलते हैं।

इसी तरह, धारा 421 की उप-धारा (4) के तहत, जो

प्रावधान 'न्यायाधिकरण के आदेशों से अपील' से संबंधित है, यह है

बशर्ते कि एनसीएलएटी, उचित अवसर देने के बाद सुना जाए तो उस पर ऐसे आदेश जारी करें जो वह उचित समझे।

'के खिलाफ अपील किए गए आदेश को बनाना, संशोधित करना या अलग करना।

इसके बाद आदेश से आगे की अपील प्रदान की जाती है

अधिनियम की धारा 423 के तहत उच्चतम न्यायालय को एन. सी. एल. ए. टी.,

2013. यहाँ, सर्वोच्च न्यायालय में अपील का दायरा है

केवल 'ऐसे आदेश से उत्पन्न होने वाले कानून के प्रश्न' तक सीमित।

17) चौथा, यह अज्ञात नहीं है बल्कि एक सामान्य विशेषता है।

जहाँ भी कोई अधिनियम हो वहाँ एक अपीलीय मंच प्रदान करने का अभ्यास

न्यायिक उपचार प्रदान करने के लिए एक पूर्ण संहिता है।

मद्रास समाज प्रदान करना v. भारत संघ €

[ए. के. सिकरी, जे.]

अपीलीय मंच के समक्ष अपील करने का अधिकार सर्वमान्य है।

मानक जिसे एक स्वस्थ परंपरा के रूप में माना जाता है।

18) इन सभी कारणों से, हम मानते हैं कि इसमें कोई योग्यता नहीं है

यह मुद्दा।

मुद्दा संख्या 2

19) एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यताएँ हैं -

अधिनियम, 2013 की धारा 409 में उल्लिखित और

एन. सी. एल. ए. टी. के अध्यक्ष और सदस्य अनुभाग में निर्धारित हैं।

411 अधिनियम, 2013 का। याचिकाकर्ता का इस बारे में कोई झगड़ा नहीं है

राष्ट्रपति और न्यायिक के लिए उल्लिखित योग्यताएँ

न्यायाधिकरण के सदस्यों के साथ-साथ अध्यक्ष और न्यायिक अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य। हालांकि, यह तर्क दिया जाता है कि

जहां तक एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के तकनीकी सदस्यों का संबंध है,

प्रावधान लगभग वही है जो इसके माध्यम से डाला गया था

अधिनियम, 1956 में एक संशोधन और उन लोगों को चुनौती प्रावधानों को विशेष रूप से इसके साथ दोष खोजने के लिए बरकरार रखा गया था। में।

इस तर्क की सराहना करने के लिए, हम तुलनात्मक दिखाते हैं

अधिनियम, 1956 के साथ-साथ अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानः

अधिनियम 1956

अधिनियम 2013

(1) 10 - FD (3) (a) (b) (c) और (d)

(1) धारा 409 (3)

(3) एक व्यक्ति योग्य नहीं होगा।

(3) एक व्यक्ति योग्य नहीं होगा।

तकनीकी पद पर नियुक्ति के लिए

तकनीकी रूप से नियुक्ति के लिए

सदस्य जब तक कि वह

सदस्य जब तक कि वह

(ए) कम से कम पंद्रह के लिए आयोजित किया गया है

((a) कम से कम पंद्रह वर्षों के लिए

समूह 'ए' पद या एक वर्ष

भारतीय सदस्य बने

केंद्रीय के तहत समकक्ष पद

निगमित विधि सेवा या भारतीय

सरकार या राज्य सरकार

कानूनी सेवा जिसमें से कम से कम

[कम से कम तीन साल

तीन साल वेतन में होंगे।

भारतीय सदस्य के रूप में सेवा

संयुक्त सचिव का पैमाना

कंपनी विधि सेवा (लेखा)

भारत सरकार या समकक्ष

शाखा) वरिष्ठ प्रशासनिक में

उस सेवा में या उससे ऊपर; या

उस सेवा में श्रेणी] या सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015

] 6 एस सी आर।

(ख) एक संयुक्त है या रहा है

((ख) व्यवहार में ऐसा है या रहा है

सरकार के सचिव

कम से कम के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट

केंद्रीय कर्मचारियों के अधीन भारत

पंद्रह वर्ष; या

योजना, या इसके तहत कोई अन्य पद

केंद्र सरकार या राज्य

सरकार वेतन का पैमाना ले रही है

जो एक जोड़ से कम नहीं है

सरकार के सचिव

भारत में कम से कम पाँच वर्षों के लिए

में, और अनुभव, के साथ काम करना कंपनी कानून से संबंधित समस्याएं,

या

(ग) कम से कम पंद्रह वर्षों से लागत लेखाकार के रूप में व्यवहार में है या रहा है।

(ग) कम से कम पंद्रह वर्षों से व्यवहार में है या रहा है

के तहत चार्टर्ड एकाउंटेंट

वर्ष; या

सनदी लेखाकार अधिनियम, 1949

(38 1949 का); या

((घ) कम से कम समय से है या रहा है

((घ) व्यवहार में ऐसा है या रहा है

एक के रूप में अभ्यास में पंद्रह साल

कम से कम कंपनी सचिव के लिए

लागत लेखाकार, लागत के तहत

पंद्रह वर्ष; या

और कार्य लेखाकार अधिनियम, 1959

(23 1959 का); या

(ई) सिद्ध क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठा वाला व्यक्ति है

पंद्रह वर्ष से कम का विशेष ज्ञान और अनुभव

कानून, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन, औद्योगिक

पु

नर्निर्माण,

निवेश, लेखांकन, श्रम मामले, या प्रबंधन, मामलों के संचालन, पुनरुद्धार, पुनर्वास और कंपनियों के समापन से संबंधित ऐसे अन्य विषय; या आई. ओ. एन. v.

(च) कम से कम पाँच के लिए है, या रहा है

वर्षों से, एक के पीठासीन अधिकारी

श्रम न्यायालय, न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय

के अधीन गठित न्यायाधिकरण

औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947।

(2) धारा 411 (3)

411 (3) एक तकनीकी सदस्य सिद्ध क्षमता, सत्यनिष्ठा और प्रतिष्ठित व्यक्ति होगा। कानून, औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन या प्रशासन में कम से कम पच्चीस वर्षों का विशेष ज्ञान और अनुभव,

पुनर्निर्माण,

औद्योगिक निवेश, लेखा, श्रम मामले, या प्रबंधन, मामलों के संचालन, पुनरुद्धार, पुनर्वास और कंपनियों के समापन से संबंधित ऐसे अन्य विषय।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015

] 6 एस सी आर।

प्रशासन,

पुनर्निर्माण, निवेश, लेखा, विपणन या

बात, विशेष

अन्य

कोई भी ज्ञान, या पेशेवर अनुभव जिसमें, होगा

केंद्र सरकार की राय

अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए उपयोगी। 20) यह इंगित किया गया था कि 2010 के फैसले में,

संविधान पीठ का विचार था कि चूंकि एन. सी. एल. टी. अब वह कार्य शुरू करें जो उच्च न्यायालय, एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. के तकनीकी सदस्यों द्वारा किया जा रहा है

केवल उन अधिकारियों में से चुना जाना चाहिए जो सचिवों या अतिरिक्त सचिवों का पद और

तकनीकी विशेषज्ञता। इन पहलुओं पर न्यायालय द्वारा चर्चा की जाती है।

निम्नलिखित अनुच्छेदों में:

" 108. विधायिका को कानून बनाने के लिए नहीं माना जाता है

कानून के शासन के विपरीत और इसलिए जानते हैं कि कहाँ विवादों का निर्णय किसी अन्य न्यायिक निकाय द्वारा किया जाना है।

न्यायालयों की तुलना में, इसके मानक लगभग होने चाहिए

जैसा कि मुख्य धारा की न्यायपालिका से अपेक्षित है।

कानून का शासन तभी सार्थक हो सकता है जब न्याय प्रदान करने के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका।

एक स्वतंत्र न्यायपालिका तभी अस्तित्व में आ सकती है जब व्यक्ति

योग्यता, क्षमता और स्वतंत्रता के साथ

न्यायिक संस्थानों का चरित्र त्रुटिहीन है।

जब विधायिका एक न्यायाधिकरण को प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव करती है

अधिकारिता का प्रयोग करने के लिए उच्च न्यायालय का स्थान जो

न्यायिक सदस्यों से अपेक्षित मानक न्यायाधिकरण और मानकों को ऐसी नियुक्ति के लिए लागू किया गया

सदस्य, जितना संभव हो उतना करीब होना चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए, जो एक बुनियादी से अलग हैं

कानून में डिग्री, के अभ्यास में समृद्ध अनुभव

कानून, स्वतंत्र दृष्टिकोण, अखंडता, चरित्र और अच्छाई प्रतिष्ठा. यह भी निहित है कि केवल स्थायी मद्रास समाज के पुरुष v.

[ए. के. सिकरी, जे.]

जिनके पास उस क्षेत्र में विशेष विशेषज्ञता है जिसके लिए

न्यायाधिकरण संबंधित है, नियुक्ति के लिए पात्र होगा

तकनीकी सदस्यों के रूप में। इसलिए, केवल एक के साथ व्यक्ति

न्यायिक पृष्ठभूमि, अर्थात वे जो रहे हैं या

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और उनके साथ वकील हैं

निर्धारित अनुभव, जो पात्र हैं

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति पर विचार किया जा सकता है

न्यायिक सदस्यों की नियुक्ति के लिए।

109. प्रशासन में जीवन भर का अनुभव हो सकता है

सिविल सेवा के सदस्य को एक अच्छा और सक्षम बनाना

प्रशासक, लेकिन जरूरी नहीं कि एक अच्छा, सक्षम और न्यायिक स्वभाव में सक्षम निष्पक्ष न्यायनिर्णायक

निर्णय के कारणों के बारे में पक्षकार; (ii) निष्पक्षता और शुद्धता का प्रदर्शन करें

निर्णय और मनमानेपन की अनुपस्थिति; और (iii)

यह सुनिश्चित करें कि न्याय न केवल किया गया है, बल्कि प्रतीत भी होता है

करने के लिए।

XX

XX

XX

111. जहाँ तक तकनीकी सदस्यों का संबंध है,

अधिकारी कम से कम सचिव स्तर का होना चाहिए

ज्ञात क्षमता और सत्यनिष्ठा के साथ अधिकारी।

नियुक्ति के लिए मानकों या योग्यताओं को कम करना।

इसके परिणामस्वरूप न्यायाधिकरणों में विश्वास की हानि होगी। हम जल्दी करते हैं।

यह जोड़ना कि हमारा इरादा यह कहना नहीं है कि व्यक्तियों के संयुक्त सचिव स्तर के लोग सक्षम नहीं हैं। यहाँ तक कि लोग भी

अवर सचिव स्तर के लोग कार्य निर्वहन के लिए सक्षम हो सकते हैं।

कार्यों को। वहाँ प्रतिभाशाली और सक्षम हो सकता है

लोग अनुभाग अधिकारी या उच्च अधिकारी के रूप में भी काम कर रहे हैं

डिवीजन क्लर्क लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे हो सकते हैं

सदस्यों के रूप में नियुक्त। योग्यता अलग है।

अनुभव, परिपक्वता और आवश्यक स्थिति से

पोस्ट करें। उदाहरण के लिए, उच्च सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट के न्यायाधीश के पद के लिए

अदालत, एक वकील के रूप में 10 साल का अभ्यास है निर्धारित किया गया। ऐसे वकील भी हो सकते हैं जिनके साथ

4 या 5 साल का अनुभव, इससे अधिक शानदार हो सकता है

10 साल की स्थिति के साथ अधिवक्ता। फिर भी ऐसा नहीं है।

अकेले क्षमता लेकिन विभिन्न अन्य कारक जो

किसी व्यक्ति को उपयुक्त बनाएँ। अतः जब

विधायिका उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रतिस्थापित करती है

न्यायाधिकरण के सदस्यों के साथ न्यायालय, मानक

लागू होने के मामले में लगभग बराबर होना चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश। इसका मतलब है कि केवल सचिव स्तर

अधिकारी (यानी वे जो सचिव या अतिरिक्त अधिकारी थे)

सचिव) विशेष ज्ञान और कौशल के साथ कर सकते हैं न्यायाधिकरण के तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाए।

XX

XX

X

X

118. कंपनी अधिनियम के भाग आई. सी. और आई. डी. का प्रस्ताव है -

कंपनी के मामलों को अदालतों से स्थानांतरित करें न्यायाधिकरण, जहाँ एक न्यायिक सदस्य 'और

' तकनीकी सदस्य विवादों का फैसला करेंगे। अगर

सदस्यों का चयन अनुभाग में विचार के अनुसार किया जाता है।

10 एफ. डी., अधिकांश की पूरी संभावना है

तथाकथित 'न्यायिक सदस्यों' सहित सदस्य नहीं

कोई न्यायिक अनुभव या कंपनी कानून होना अनुभव और ऐसे सदस्यों को सौदा करने की आवश्यकता है

तथ्य और कानून के जटिल मुद्दों के साथ निर्णय लेना। क्या

न्यायाधिकरणों में केवल न्यायिक सदस्य होने चाहिए या

न्यायिक और तकनीकी सदस्यों के संयोजन का निर्णय विधानमंडल को करना है। लेकिन अगर ऐसा होना चाहिए।

तकनीकी सदस्य होने के कारण, वे ऐसे व्यक्ति होने चाहिए जिनके साथ

कंपनी कानून या संबद्ध विषयों में विशेषज्ञता और केवल

सिविल सेवा में अनुभव को ऐसा नहीं माना जा सकता है कंपनी कानून में तकनीकी विशेषज्ञता। इन उम्मीदवारों

उप-धारा 2 (ग) और (घ) और उप-धाराओं के अंतर्गत आने वाली

3 (धारा 10 एफडी के क) और (ख) के पास कोई अनुभव या अनुभव नहीं है।

कंपनी के मामलों को तय करने में विशेषज्ञता।

मद्रास समाज बनाम। भारत का संघ

{

[ए. के. सिकरी, जे.]

119. एक गलत धारणा है कि कंपनी

न्यायाधीशों की कमी है। वहाँ भी एक समान है गलत धारणा है कि नागरिक के सदस्य

कंपनी कानून में विशेषज्ञता या तो नियुक्त की जाएगी न्यायिक सदस्य या तकनीकी सदस्य के रूप में। न ही कर सकते हैं।

पंद्रह वर्ष का अनुभव रखने वाले व्यक्ति

विज्ञान, प्रौद्योगिकी, चिकित्सा, बैंकिंग, उद्योग

के लिए कंपनी कानून में विशेषज्ञ के रूप में कहा जा सकता है

तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाना। अभ्यास

तकनीकी सदस्यों के रूप में विशेषज्ञों का होना उपयुक्त है।

जिन क्षेत्रों में पेशेवरों की सहायता की आवश्यकता है

विशेषज्ञ, चिकित्सा, इंजीनियरिंग में योग्य, और वास्तुकला आदि। अंत में, हम इसकी कमी का उल्लेख कर सकते हैं

कार्यकाल की सुरक्षा। तीन वर्ष की अल्पावधि, जांच लंबित रहने तक नियमित निलंबन का प्रावधान और

किसी भी प्रकार की प्रतिरक्षा की कमी, ऐसे पहलू हैं जो

इस पर विचार करने और सुधार करने की आवश्यकता है।

21) उपरोक्त चर्चाओं के आधार पर, भाग 1 सी

और अधिनियम, 1956 का 1 डी, जैसा कि वे मौजूद थे, अमान्य माना गया। और इन प्रावधानों को दायरे में लाने के लिए

संवैधानिकता, न्यायालय ने उन सुधारों की ओर इशारा किया जो

उन एनामोलियों को हटाने के लिए बनाया जाना आवश्यक था। पैरा

120 इस मुद्दे का जवाब देने के लिए निर्णय सबसे अधिक प्रासंगिक है

हाथ और इसलिए, हम उक्त पैरा को पूरी तरह से पुनः प्रस्तुत करते हैं:

" 120. हम सेट करने के लिए आवश्यक सुधारों को सारणीबद्ध कर सकते हैं अधिनियम के भाग आईबी और आईसी में दोषों को ठीक करनाः

(i) केवल न्यायाधीशों और अधिवक्ताओं पर विचार किया जा सकता है।

न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए।

केवल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, या न्यायाधीश जिन्होंने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट में काम किया है

कम से कम पाँच वर्ष के लिए जिला न्यायाधीश के पद पर या वह व्यक्ति जिसने दस साल तक वकील के रूप में काम किया है, कर सकता है

केंद्र या राज्य सरकार के अधीन पद भारतीय कंपनी विधि सेवा में अनुभव (कानूनी)

शाखा) और भारतीय कानूनी सेवा (ग्रेड-1) नहीं हो सकती है

न्यायिक सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया गया जैसा कि धारा की उप-धारा 2 (ग) और (घ) में दिया गया है।

10 एफ. डी. कंपनी विधि सेवा में विशेषज्ञता या

भारतीय कानूनी सेवा उन्हें सर्वोत्तम रूप से सक्षम बनाएगी

(ii) जैसा कि एन. सी. एल. टी. उच्च के कार्यों को संभालता है। न्यायालय, सदस्यों को जितना संभव हो उतना होना चाहिए

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान स्थिति और स्थिति। यह

इसे प्राप्त किया जा सकता है, न कि वेतन और भत्ते देकर सदस्यों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, लेकिन यह सुनिश्चित करके कि

ऐसे व्यक्ति जो पद, अनुभव या योग्यता में लगभग बराबर हैं।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता के रूप में नियुक्त किया जाता है सदस्य। इसलिए, केवल वे अधिकारी जो धारण कर रहे हैं

सचिवों या अतिरिक्त सचिवों के पद

अकेले नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है

राष्ट्रीय कंपनी कानून के तकनीकी सदस्य न्यायाधिकरण। उप-धारा (2) के खंड (ग) और (घ) और

धारा 10 एफडी की उप-धारा (3) के खंड (ए) और (बी)

जो 15 वर्ष के अनुभव वाले व्यक्तियों के लिए प्रदान करता है

समूह ए पद या संयुक्त पद धारण करने वाले व्यक्ति

केंद्रीय या राज्य में सचिव या समकक्ष पद

(iii) एक 'तकनीकी सदस्य' का अनुमान है कि उस क्षेत्र में अनुभव जिससे न्यायाधिकरण संबंधित है।

भारतीय कंपनी विधि सेवा का एक सदस्य जिसने

लेखा शाखा या अन्य मद्रास बार एसोसिएशन में अधिकारियों के साथ काम किया।

[ए. के. सिकरी, जे.]

तकनीकी के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य 'विशेषज्ञों' के रूप में सदस्य। अतः उप-धारा के खंड (क) और (ख)

(3) वैध नहीं हैं।

((iv) उप-धारा (3) के खंड (च) का पहला भाग

कि कोई भी व्यक्ति जिसके पास विशेष ज्ञान या पेशेवर है

विज्ञान, प्रौद्योगिकी में 20 वर्षों का अनुभव,

अर्थशास्त्र, बैंकिंग, उद्योग को माना जा सकता है

कंपनी कानून में विशेषज्ञता वाले व्यक्ति, होने के लिए कंपनी कानून में तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्त

न्यायाधिकरण, अमान्य है।

(v) क्षमता, सत्यनिष्ठा, प्रतिष्ठा और विशेष क्षमता वाले व्यक्ति।

ज्ञान और पेशेवर अनुभव कम नहीं

औद्योगिक वित्त, औद्योगिक क्षेत्र में पंद्रह वर्ष से अधिक

कंपनियां और इसलिए, होने के लिए पात्र तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया गया।

(vi) खंड में निर्दिष्ट व्यक्तियों की श्रेणी के संबंध में (छ) उप-धारा (3) का कम से कम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिए।

निर्दिष्ट करें।

(vii) केवल खंड (सी), (डी), (ई), (जी), (एच), और बाद के भाग

धारा 10 एफडी की उप-धारा (3) में खंड (च) और अधिकारी

सचिव या अतिरिक्त रैंक की सिविल सेवाओं की भारतीय कंपनी विधि सेवा में सचिव और

भारतीय विधि सेवा सेवा पर तकनीकी सदस्यों के रूप में नियुक्ति के उद्देश्यों के लिए विचार किया जा सकता है

न्यायाधिकरण।

(viii) पांच सदस्यीय चयन समिति के बजाय

अध्यक्ष के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश (या उनके नामित) सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

और वित्त मंत्रालय के दो सचिव और कंपनी कार्य और मंत्रालय में सचिव

श्रम और कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव

धारा 10 एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में, चयन समिति को मोटे तौर पर निम्नलिखित तर्ज पर होना चाहिएः

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष

उच्च न्यायालय के-सदस्य; (ग) वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव

कार्य-सदस्य; और

(घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव-सदस्य।

(ix) तीन साल के कार्यकाल को बदल दिया जाएगा

विशेषज्ञता प्राप्त करने के लिए काफी समय की आवश्यकता होती है संबंधित क्षेत्र। तीन साल की अवधि बहुत है।

कम समय में और जब तक सदस्य प्राप्त करते हैं

आवश्यक ज्ञान, विशेषज्ञता और दक्षता, एक कार्यकाल

खत्म हो जाएगा। इसके अलावा तीन साल की उक्त अवधि

65 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु के रूप में माना जाता है

उन व्यक्तियों के लिए तैयार किया गया है जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं या

शीघ्र ही सेवानिवृत्त हो जाएँगे और इन न्यायाधिकरणों को प्रोत्साहित करेंगे

सेवानिवृत्ति के बाद के स्वर्ग के रूप में माना जाए। यदि इन न्यायाधिकरणों को प्रभावी ढंग से और कुशलता से काम करना है

उन्हें युवा सदस्यों को आकर्षित करने में सक्षम होना चाहिए जो

सेवा की एक उचित अवधि हो।

(x) धारा 10 एफई के लिए दूसरा परंतुक राष्ट्रपति और सदस्यों को उनके साथ ग्रहणाधिकार बनाए रखना

पद धारण करते समय मूल संवर्ग/मंत्रालय/विभाग

अध्यक्ष या सदस्यों के रूप में मद्रास समाज अनुकूल नहीं होगा।

सदस्यों की स्वतंत्रता के लिए। कोई भी व्यक्ति।

सदस्यों के रूप में नियुक्त होने के लिए पूरी तरह से तैयार होना चाहिए

कार्यपालिका से खुद को अलग कर लें। ग्रहणाधिकार नहीं हो सकता है

इसलिए यह एक वर्ष की अवधि से अधिक है।

(xi) सेवा में स्वतंत्रता और सुरक्षा बनाए रखने के लिए,

धारा 10 एफजे और धारा 10 एफवी की उप-धारा (3)

राष्ट्रपति के निलंबन का प्रावधान करना चाहिए /

न्यायाधिकरण का अध्यक्ष या सदस्य केवल हो सकता है

भारत के मुख्य न्यायाधीश की सहमति से।

(xii) सभी न्यायाधिकरणों के लिए प्रशासनिक सहायता कानून और न्याय मंत्रालय से होना चाहिए। न ही

न्यायाधिकरण और न ही इसके सदस्य मांगेंगे या प्रदान किए जाएंगे संबंधित प्रायोजक से सुविधाओं के साथ या

मूल मंत्रालय या संबंधित विभाग।

(xiii) न्यायाधिकरण की दो-सदस्य पीठों को हमेशा ऐसा करना चाहिए

एक न्यायिक सदस्य रखें। जब भी कोई बड़ा या

विशेष पीठों का गठन किया जाता है, जिनकी संख्या

तकनीकी सदस्य न्यायिक सीमा से अधिक नहीं होंगे।

सदस्यों "।

22) पैरा 120 के पढ़ने से क्या पता चलता है,

विशेष रूप से, उप-पैरा (ii) कि केवल वे अधिकारी जो

सचिवों या अतिरिक्त सचिवों के पद धारण करना

केवल तकनीकी के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाना है एन. सी. एल. टी के सदस्य। खंड (ग) में निहित प्रावधान और

(घ) उप-धारा (2) और उप-धारा (3) के खंड (क) और (ख)

धारा 10 एफ. डी. जो कुछ विशिष्टताओं के साथ संयुक्त सचिव बनाती है

योग्य अनुभव को विशेष रूप से अमान्य घोषित किया गया था।

इसके बावजूद, अधिनियम, 2013 की धारा 409 (3)

पुनः भारत सरकार का संयुक्त सचिव बनाता है या नियुक्ति के लिए पात्र समकक्ष अधिकारी, यदि उसकी आयु 15 वर्ष है।

भारतीय निगमित विधि सेवा के सदस्य के रूप में अनुभव या

भारतीय कानूनी सेवा, जिसमें से कम से कम 3 साल का अनुभव उच्च न्यायालय रिपोर्ट का हो।

[2015

] 6 एस सी आर।

संयुक्त सचिव के वेतनमान में। यह स्पष्ट रूप से 2010 के फैसले में घोषित डिक्टा के दांतों में है।

23) जवाबी हलफनामे में, उत्तरदाताओं ने

यह कहते हुए इस प्रावधान को सही ठहराने का प्रयास किया कि यह भिन्नता

अतिरिक्त में उपलब्ध अधिकारियों की कमी को देखते हुए बनाया गया था

भारतीय कंपनी विधि सेवा में सचिव स्तर। यह आगे है

उल्लेख किया कि कार्यात्मक रूप से अतिरिक्त सचिव के स्तर

और संयुक्त सचिव समान हैं। इन अधिकारियों के पास ज्ञान है।

संचालन और कार्य से संबंधित विशिष्ट मुद्दों का

कम्पनियाँ और कम्पनी कानून में उनकी विशेषज्ञता जो है इससे एन. सी. एल. टी. को लाभ होने की उम्मीद है। इस तरह का स्पष्टीकरण कानूनी नहीं है।

टिकाऊ, 2010 के स्पष्ट जनादेश को ध्यान में रखते हुए

निर्णय।

हम यह बताना चाहेंगे कि अन्य देने के अलावा

ऐसे पदों के लिए विचार को सीमित करने के कारण

सचिव और अतिरिक्त सचिव, वहाँ एक बहुत था

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जिसे एक मामले के रूप में माना जाता था चिंता की बात है। इस पहलू को विशिष्ट रूप से प्रदर्शित किया गया था

व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानकों और योग्यताओं के क्रमिक कमजोर होने को दर्शाने वाले कुछ अधिनियमों में उदाहरण

उन मामलों का निर्णय लें जो पहले उच्च न्यायालय द्वारा तय किए जा रहे थे अदालत। इस प्रकार, हम इसे पुनः प्रस्तुत करना उचित समझते हैं कि

चर्चा जो उपरोक्त का पूर्ण उत्तर प्रदान करती है

उत्तरदाताओं द्वारा लिया गया तर्क। उक्त चर्चा,

पैरा 112 में इसके उप-पैरा के साथ निम्नलिखित लिखा गया है:

" 112. धीरे-धीरे क्षरण चिंता का विषय है।

न्यायपालिका की स्वतंत्रता, और का सिकुड़ना

न्यायपालिका द्वारा कब्जा किया गया स्थान और धीरे-धीरे

संबंधित व्यक्तियों की संख्या में वृद्धि

सिविल सेवा कार्य निर्वहन और अभ्यास

अधिकारिता जिसका प्रयोग पहले किया गया था

उच्च न्यायालय। मद्रास बार एसोसिएशन v का धीरे-धीरे कमजोर होना भी है।

भारत का संघ

एफ.

[ए. के. सिकरी, जे.]

व्यक्तियों के लिए निर्धारित मानक और योग्यता

जिन मामलों का निर्णय पहले किया जा रहा था

उच्च न्यायालय। आइए हम समीक्षा करें।

112.1 शुरू करने के लिए, संबंधित क्षेत्राधिकार के अलावा

दीवानी, आपराधिक और कर में अपील और संशोधन

मामले (और कुछ उच्च न्यायालयों में मूल नागरिक अधिकार क्षेत्र)

अदालतें)। उच्च न्यायालय मूल प्रयोग कर रहे थे

दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अधिकार क्षेत्र; एक रिट था

अनुच्छेद 226 और 227 के तहत अधिकारिता (सहित)

सेवा मामलों में मूल अधिकार क्षेत्र) और

अन्य कंपनी के मामलों के संबंध में था।

112.2 प्रशासनिक न्यायाधिकरणों के गठन के बाद

प्रशासनिक न्यायाधिकरण अधिनियम, 1985 अधिकारिता

सेवा से संबंधित मूल अधिकार क्षेत्र के संबंध में

मामलों को उच्च न्यायालयों से स्थानांतरित किया गया था

प्रशासनिक न्यायाधिकरण। उक्त अधिनियम की धारा 6 से संबंधित है। अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताओं के साथ, और यह

इससे यह स्पष्ट है कि सभापति को एक उच्च अधिकारी होना चाहिए। न्यायालय के न्यायाधीश या तो वर्तमान या पूर्व न्यायाधीश होते हैं। न्यायपालिका के लिए

सदस्य की योग्यता यह थी कि वह एक न्यायाधीश होना चाहिए

उच्च न्यायालय का या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है।

न्यायालय (अर्थात दस वर्ष के साथ उच्च न्यायालय का एक अधिवक्ता)

दस के लिए एक न्यायिक पद का अभ्यास या धारक

वर्ष) या सचिव का पद धारण करने वाला व्यक्ति,

सरकार. भारत के कानूनी मामलों के विभाग में या

विधायी विभाग या सदस्य सचिव, कानून

दो वर्ष की अवधि के लिए भारत का आयोग; या

में भारत सरकार के अतिरिक्त सचिव

कानूनी कार्य या विधायी विभाग

पाँच वर्ष की अवधि के लिए विभाग। 112.3 प्रशासनिक सदस्य के रूप में नियुक्त होने पर,

योग्यता यह थी कि उम्मीदवार को

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट की सरकार के सचिव के रूप में कार्य किया है

भारत या केंद्रीय या राज्य का कोई अन्य पद

सरकार वेतन का पैमाना वहन करती है जो कम नहीं है

कम से कम भारत सरकार के सचिव के रूप में

दो वर्ष, या अतिरिक्त के पद पर होना चाहिए था

भारत सरकार के सचिव या कोई अन्य

पाँच साल से। दूसरे शब्दों में, जिन मामलों पर निर्णय लिया गया था उच्च न्यायालयों द्वारा एक न्यायाधिकरण द्वारा निर्णय लिया जा सकता है जिसका

सदस्य सचिव स्तर के दो अधिकारी हो सकते हैं।

दो साल का अनुभव या दो अतिरिक्त सचिव भी।

पाँच वर्ष के अनुभव वाले स्तर के अधिकारी। यह था।

पहला डाइल्यूशन।

112.4 सदस्यों को एक कार्यकाल प्रदान किया गया था

पाँच साल का पद और 65 साल तक पद धारण कर सकता है।

और इन सदस्यों का वेतन और अन्य अनुलाभ

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान बनाए गए थे। यह

स्वयं एक टिप्पणी के लिए जगह दी कि ये पोस्ट थे

वस्तुतः सदस्यों के लिए अनिश्चित के रूप में बनाया गया कार्यपालक अपनी सेवा की अवधि को पांच गुना बढ़ाएंगे

उच्च के लिए लागू उच्च वेतन पर 60 से 65 वर्ष

न्यायालय के न्यायाधीश। कार्यपालिका के कुछ सदस्य

इस प्रकार वे अभ्यास करने वाले न्यायाधिकरणों के सदस्य बन गए

न्यायिक कार्य "।

112.5 हम आगे सूचना प्रौद्योगिकी का उल्लेख कर सकते हैं।

अधिनियम, 2000 जो साइबर की स्थापना के लिए प्रावधान करता है

एकल सदस्य के साथ अपीलीय न्यायाधिकरण। धारा 50

उस अधिनियम में यह प्रावधान किया गया है कि एक व्यक्ति जो है, या रहा है, या

उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए योग्य है, या वह व्यक्ति जो भारत विधि आयोग का सदस्य है या रहा है

सेवा कर रहा है और के ग्रेड I में एक पद धारण किया है या किया है

कम से कम तीन साल की सेवा के लिए मद्रास बार एसोसिएशन V नियुक्त किया जा सकता है।

पीठासीन अधिकारी के रूप में। अर्थात्, सम की आवश्यकता

एक सचिव स्तर का अधिकारी चला गया है। कोई भी सदस्य

ग्रेड-I पद धारण करने वाली भारतीय कानूनी सेवा

तीन साल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का विकल्प हो सकता है।

112.6 अगला मंदन अध्यायों को सम्मिलित करके होता है।

1 बी कंपनी अधिनियम, 1956 से प्रभावी

1.4.2003 राष्ट्रीय कंपनी के गठन का प्रावधान

एक अध्यक्ष और एक बड़ी संख्या के साथ विधि न्यायाधिकरण

न्यायिक और तकनीकी सदस्य (अधिकतम 62)।

योग्यताओं में और कमी आई है

राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण के सदस्य जो एक

समापन सुनवाई के लिए उच्च न्यायालय का विकल्प

भारत का या केंद्र और राज्य के अधीन कोई पद धारण करने वाला सरकार वेतन का एक पैमाना वहन करती है जो इससे कम नहीं है

भारत सरकार के संयुक्त सचिव) के लिए

पाँच साल की अवधि योग्य है। इसके अलावा, कोई भी व्यक्ति

जिसने 15 वर्षों के लिए समूह-ए पद संभाला है (जो

मतलब भारतीय पी एंड टी खातों से संबंधित कोई भी व्यक्ति। & वित्त सेवा, भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा

सेवा, भारतीय सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क सेवा, भारतीय रक्षा लेखा सेवा, भारतीय राजस्व

सेवा, भारतीय आयुध निर्माणी सेवा, भारतीय डाक सेवा, भारतीय सिविल लेखा सेवा, भारतीय

रेलवे यातायात सेवा, भारतीय रेलवे लेखा

संपदा सेवा, भारतीय सूचना सेवा, भारतीय व्यापार सेवाएं, या अन्य केंद्रीय या राज्य सेवा) तीन के साथ

भारतीय कंपनी के सदस्य के रूप में सेवा के वर्षों

विधि सेवा (लेखा) शाखा, या जिसने सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्टों को 'निपटाया' है

[2015

] 6 एस सी आर।

कंपनी कानून से संबंधित किसी भी समस्या के साथ हो सकता है

एक सदस्य। इसका मतलब है कि जो मामले थे

उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा निर्णय लिया जा सकता है सिविल सेवा के दो सदस्यों द्वारा-संयुक्त सचिव

समूह 'क' पदों पर आसीन अधिकारी या अधिकारी या 15 साल के लिए समकक्ष पद, अब निर्वहन कर सकते हैं

उच्च न्यायालय के कार्य। इसने फिर से जगह दी है।

यह टिप्पणी करने के लिए कि निर्धारित योग्यताएं दर्जी हैं

जोड़ों की एक बड़ी संख्या के लिए अनिश्चित प्रदान करने के लिए बनाया गया सचिव स्तर के अधिकारी या समूह 'ए' पदों पर आसीन अधिकारी

न्यायिक कार्य करने वाले न्यायाधिकरणों में 65 वर्ष तक सेवा करने के लिए कार्य।

112.7 मानकों का कमजोर होना यहीं खत्म नहीं हो सकता है। द.

प्रस्तावित कंपनी विधेयक, 2008 में विचार किया गया है कि भारतीय कानूनी सेवा या भारतीय कंपनी कानून के सदस्य

केवल दस साल की सेवा के साथ सेवा (कानूनी शाखा),

जिनमें से तीन वर्ष के वेतनमान में होना चाहिए

संयुक्त सचिव, न्यायिक के रूप में नियुक्त होने के लिए योग्य है

सदस्यों के रूप में नियुक्ति को कम किया जा रहा है, कहने के लिए कम से कम, स्वतंत्रता के लिए बहुत चिंता का विषय

न्यायपालिका "।

24) उपरोक्त को स्पष्ट और स्पष्ट रूप से ध्यान में रखते हुए

2010 के फैसले में स्पष्ट रूप से इसके साथ छेड़छाड़ की गई होगी।

मानकों के साथ समझौता करने की क्षमता जो 2010

न्याय ने हासिल करने की कोशिश की, नहीं, इसलिए उत्साह से सुरक्षित करने की कोशिश की।

इस प्रकार, हम मानते हैं कि धारा 409 (3) (ए) और (सी) अमान्य हैं क्योंकि

ये प्रावधान एक ही बुराई से ग्रस्त हैं। इसी तरह, अनुभाग 411 (3) जैसा कि कहा जाता है, तकनीकी योग्यताओं का प्रावधान

सदस्यों को भी अमान्य माना जाता है। नियुक्ति के लिए

एन. सी. एल. टी. के तकनीकी सदस्यों को 2010 के निर्णय के पैरा 120 के उप पैरा (ii), (iii) ', (iv), (v) में निहित निर्देशों का पालन करना होगा।

ईमानदारी से पालन किया जाए और इन सुधारों की आवश्यकता है मद्रास बार एसोसिएशन v।

भारत का संघ

ई.

[ए. के. सिकरी, जे.]

धारा 409 (3) में निहित दोषों को ठीक करने के लिए

उसमें। हम निर्गम संख्या 2 का निपटान करते हुए तदनुसार आदेश देते हैं।

इश्यू नंबर 3 25) यह मुद्दा चयन के संविधान से संबंधित है।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. सदस्यों के चयन के लिए समिति। इस संबंध में प्रावधान की धारा 412 में निहित है

अधिनियम, 2013। उप-धारा (2) में चयन का प्रावधान है।

समिति में शामिल हैंः

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष;

((b) उच्चतम न्यायालय का कोई वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के-सदस्य;

(ग) निगमित कार्य मंत्रालय में सचिव-सदस्य; (घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव-सदस्य;

और (ई) वित्तीय विभाग में सचिव वित्त मंत्रालय में सेवाएं-सदस्य।

इस संबंध में प्रावधान जो धारा में निहित था

10 एफएक्स, इसकी वैधता पर 2010 के फैसले में सवाल उठाया गया था,

निम्नलिखित प्रभाव के लिएः

" 10 एफएक्स। चयन समितिः (1) अध्यक्ष

और अपीलीय न्यायाधिकरण के सदस्य और

न्यायाधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य होंगे

केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त चयन समिति की सिफारिशें

सेः

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत अध्यक्ष;
(ख) वित्त मंत्रालय में सचिव और

सदस्य; कंपनी मामले

(ग) श्रम मंत्रालय में सचिव सदस्य; सर्वोच्च न्यायालय रिपोर्ट

एस सी आर।

((घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव (कानूनी कार्य या विधायी विभाग

विभाग) सदस्य;

(ई) वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव

कार्य (कंपनी कार्य विभाग) सदस्य।

(2) मंत्रालय या विभाग में संयुक्त सचिव इस अधिनियम से निपटने वाली केंद्र सरकार का होगा

चयन समिति के संयोजक "।

26) चयन समिति की उपरोक्त संरचना

जैसा कि 2010 के फैसले में संविधान पीठ द्वारा दोष पाया गया था।

ई न्यायालय ने विशेष रूप से टिप्पणी की कि 5 सदस्यों के बजाय

समिति को पैरा 120 के निर्देश सं. (viii) में अनिवार्य किया गया था।और इस उप-पैरा को हम एक बार फिर यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत करते हैंः

" (viii) पांच सदस्यीय चयन समिति के बजाय

और वित्त मंत्रालय के दो सचिव और कंपनी कार्य और मंत्रालय में सचिव

श्रम और कानून और न्याय मंत्रालय में सचिव

धारा 10 एफएक्स में उल्लिखित सदस्यों के रूप में, चयन

समिति को मोटे तौर पर निम्नलिखित तर्ज पर होना चाहिएः

(क) भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत-अध्यक्ष (एक निर्णायक वोट के साथ);

(ख) उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठ न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश

उच्च न्यायालय के-सदस्य;

(ग) वित्त और कंपनी मंत्रालय में सचिव

कार्य-सदस्य; और

((घ) विधि और न्याय मंत्रालय में सचिव

— मद्रास समाज बनाम। यूनियन ऑफ इंडिया एफ

[ए. के. सिकरी, जे.]

सदस्य "।

27) उपरोक्त के बावजूद, इसमें एक विचलन है

चयन समिति की संरचना जो इसके तहत निर्धारित की गई है

अधिनियम, 2013 की धारा 412 (2)। विचलन निम्नानुसार हैंः

(i) यद्यपि भारत के मुख्य न्यायाधीश या उनके मनोनीत व्यक्ति हैं -

अध्यक्ष के रूप में कार्य करने के लिए, उसे कास्टिंग की शक्ति नहीं दी जाती है वोट करें। इसका कारण यह है कि चार सदस्यों के बजाय

समिति, विवादित में समिति की संरचना प्रावधान पाँच सदस्यों का है।

((ii) इस न्यायालय ने एक सदस्य का सुझाव दिया था जो ऐसा कर सकता था।

वित्त मंत्रालय में या कंपनी में सचिव बनें

मामले (हम इंगित कर सकते हैं कि शब्द "और" में निहित है

ऐसा प्रतीत होता है कि पैरा 120 के उप-पैरा (viii) का खंड (ग)

टाइपोग्राफिक गलती और इसे "या" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए, अन्यथा

इसका कोई मतलब नहीं होगा)।

(iii) अब, दोनों मंत्रालयों से, अर्थात्

निगमित कार्य मंत्रालय के साथ-साथ वित्त मंत्रालय, प्रत्येक में एक सदस्य शामिल है। इस रचना का प्रभाव यह है कि

इसे पाँच सदस्यीय चयन समिति बनाएँ जो नहीं थी 2010 के फैसले में वैध पाया गया। कारण सरल है,

ये पाँच सदस्य, तीन प्रशासनिक शाखा से हैं /

न्यायपालिका से दो के खिलाफ नौकरशाही जिसका परिणाम होगा

संबंधित सदस्यों का प्रमुख कहना

प्रशासनिक शाखा, ऐसी स्थिति है जिसे विशेष रूप से मोड़ दिया गया था

से।

चयन समिति की संरचना में निहित है

अधिनियम, 2013 की धारा 412 (2) को न्यायसंगत ठहराने की मांग की गई है।

उत्तरदाताओं ने तर्क दिया कि अनुशंसित रचना

2010 का फैसला व्यापक रूप से था। यह तर्क दिया जाता है कि बी. आई. एफ. आर. और ए. ए. आई. एफ. आर. को शामिल करने का दृष्टिकोण

वित्तीय सेवा विभाग का प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र, सचिव डी. एफ. एस. को शामिल किया गया है। कोई निर्णायक मत सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट नहीं रही है

[2015

] 6 एस सी आर।

अध्यक्ष के लिए समय की अवधि के रूप में प्रावधान किया गया

ऐसी समितियों में चयन प्रक्रियाएँ एक में स्पष्ट हो गई हैं

जिस तरह से सिफारिशें सर्वसम्मत रही हैं और

मंत्रालय में ऐसी समितियों में मतदान का कोई उदाहरण नहीं है

निगमित मामले। इसके अलावा अन्य समान वैधानिक निकाय /

न्यायाधिकरणों में भी अध्यक्ष को 'मतदान करने' का प्रावधान नहीं है

चयन समिति। इसके अलावा, समिति होगी अधिनियम में दिए गए अपने तौर-तरीकों का निर्धारण करना। द.

इस प्रावधान को सही ठहराने के लिए निम्नलिखित तर्क भी उठाए गए हैं: ((i)

विचार-विमर्श में मजबूत और स्वस्थ प्रथाओं का विकास हुआ है

चयन समितियाँ। अब तक कोई ज्ञात मामला नहीं है

ऐसी समितियों में भौतिक असहमति। ((ख) इरादा संबंधित व्यक्तियों के साथ चयन समिति का संचालन करना है

अनुभव और ज्ञान।

28) हमारी राय है कि यह फिर से गठित नहीं होता है।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कोई वैध या कानूनी औचित्य कि

बहुत ही मुद्दा 2010 के फैसले से समाप्त हो गया है जो है

अब एक बाध्यकारी पूर्ववर्ती है और इस प्रकार, प्रतिवादी को बांधता है समान रूप से। पीठ के दिमाग में मुख्य विचार

यह था कि वह अध्यक्ष है, अर्थात। भारत के मुख्य न्यायाधीश, या उनके

नामित व्यक्ति जिसे मामले में अंतिम निर्णय दिया जाना है

मतदान करने के अधिकार के साथ चयन। यह अनुपात है कि

निर्णय और ऐसी रचना प्रदान करने के कारण

खोजने के लिए बहुत दूर नहीं हैं। सभी व्यापक निर्देश के सामने

इस मुद्दे पर एक बाध्यकारी मिसाल के रूप में उपलब्ध,

किसी भी छूट के लिए कोई गुंजाइश नहीं है जैसा कि प्राप्त करने की मांग की गई है

विवादित प्रावधान के माध्यम से और हम इसे पाते हैं

2010 के निर्णय के अनिवार्य आदेश के साथ असंगत। इसलिए, हम मानते हैं कि धारा 412 (2) के प्रावधान

अधिनियम, 2013 वैध नहीं है और इसे हटाने के लिए निर्देश जारी किए गए हैं। उप-पैरा (viii) के अनुसार इस प्रावधान को लाने में दोष

2010 के निर्णय के पैरा 120 का।

29) अब हम मद्रास बार एसोसिएशन v में उठाए गए कुछ अन्य मुद्दों पर विचार करते हैं।

भारत का संघ

ई.

[ए. के. सिकरी, जे.]

याचिका। श्री दातार द्वारा यह तर्क दिया गया था कि दंडित करने की शक्ति

धारा के तहत एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को दी गई अवमानना के लिए

425 अधिनियम स्वस्थ नहीं है और इसे समाप्त कर दिया जाना चाहिए। यह.

यह भी तर्क दिया गया कि केंद्र सरकार को शक्ति दी गई थी

पीठों का गठन करना फिर से अस्वीकार्य है

शक्ति अध्यक्ष, एन. सी. एल. टी. या अध्यक्ष, एन. सी. एल. ए. टी. के पास होनी चाहिए।

हालाँकि, हमें इन तर्कों में शायद ही कोई कानूनी ताकत मिलती है।

हमें यह ध्यान रखना होगा कि ये प्रावधान निहित हैं।

संसद द्वारा अधिनियमित कानून में और याचिकाकर्ता कर सकता है

यह नहीं बताते कि ऐसे प्रावधान कैसे असंवैधानिक हैं।

30) उपरोक्त चर्चा का परिणाम यह है कि इसकी अनुमति दी जाए

आंशिक रूप से रिट याचिका, ऊपर उल्लिखित तरीके से।

31) अलग होने से पहले, हमें यह उल्लेख करना चाहिए कि शपथ पत्र

दिनांकित 07.05.2015 उत्तरदाताओं की ओर से दायर किया गया है

इसमें अब तक उठाए गए कदमों का उल्लेख किया गया है।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. की स्थापना की दिशा में। यह बताया गया है कि

अध्यक्ष के एक पद और पाँच पद के सृजन के लिए मंजूरी

एन. सी. एल. ए. टी. के सदस्यों के पदों के साथ-साथ अध्यक्ष का एक पद

और एन. सी. एल. टी. के सदस्यों के 62 पद और पंजीयक के दो पद

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के लिए एक-एक और सचिव का एक पद, एन. सी. एल. टी. प्राप्त की गई थी और इसके लिए मंजूरी भी प्राप्त की गई थी।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. में सहायक कर्मचारियों के 246 पदों का सृजन।

विधायी विभाग के परामर्श से तैयार किया गया, विधि मंत्रालयः (i) एन. सी. एल. ए. टी. (वेतन, भत्ता और अन्य)

अध्यक्ष और अन्य की सेवा के नियम और शर्तें

सदस्य) नियम, 2014, (ii) एन. सी. एल. टी. (वेतन, भत्ते और अन्य)

राष्ट्रपति और अन्य की सेवा के नियम और शर्तें

सदस्य) नियम, 2013। भर्ती नियमों का मसौदा

सहायक कर्मचारियों को भी परामर्श से तैयार किया गया था

विधायी विभाग, विधि मंत्रालय। आगे इसका उल्लेख किया गया है।

एन. सी. एल. टी. के काम करने के तरीके के संबंध में नियमों का मसौदा /

एन. सी. एल. ए. टी. आदि तैयार किए गए थे ताकि उन्हें पहले रखा जा सके

एन. सी. एल. ए. टी./एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष/अध्यक्ष की उनकी नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2015

] 6 एस सी आर।

कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अंतिम रूप देने के लिए,

2013. इन नियमों में इस तरह के प्रावधान शामिल हैं -

एन. सी. एल. टी./एन. सी. एल. ए. टी. की कार्यप्रणाली; आवेदन करने का तरीका

आवेदकों द्वारा विभिन्न अनुमोदन किए जाएंगे और उन्हें मंजूरी दी जाएगी।

समामेलन; उत्पीड़न की रोकथाम और कुप्रबंधन; बीमार कंपनियों का पुनरुद्धार और पुनर्वास;

समापन और अन्य विविध आवश्यकताएँ। इसके लिए जगह

एन. सी. एल. टी. की प्रधान पीठ और अन्य पीठ, जिनमें एक

बी. आई. एफ. आर. के स्थानांतरित मामलों से निपटने के लिए दिल्ली में विशेष पीठ

और ए. ए. आई. एफ. आर. की भी पहचान की गई थी। शुरू की गई प्रक्रिया

कुछ स्थानों पर किराए की जगह, जिसे बंद कर दिया गया था

लंबित याचिका का अवलोकन, थोड़े समय की सूचना पर फिर से शुरू किया जा सकता है।

खर्च को पूरा करने के लिए बजट शीर्ष बनाए गए हैं।

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. के लिए 2014-2015 के लिए आवंटित धन चाहिए था न्यायाधिकरणों के निपटारे में देरी को देखते हुए समर्पण किया जाए।

32) उपरोक्त से, यह एकमात्र कदम प्रतीत होता है जो है

एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. को कार्यात्मक बनाने के लिए नियुक्ति करनी है।

एन. सी. एल. टी. के अध्यक्ष और सदस्य तथा अध्यक्ष और

एन. सी. एल. ए. टी के सदस्य।

33) तब से, एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी. ने काम नहीं किया है।

अब तक शुरू हुआ और यह उच्च समय है कि ये न्यायाधिकरण शुरू हों

अब काम कर रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं कि उत्तरदाता लेंगे

इसमें निहित निर्देशों के अनुसार उपचारात्मक उपाय

जल्द से जल्द निर्णय लें, ताकि एन. सी. एल. टी. और एन. सी. एल. ए. टी.

पर्याप्त रूप से मानवयुक्त और निकट भविष्य में काम करना शुरू करें।

34) लिखित याचिका का निपटारा उपरोक्त में किया गया है।

तरीके से।

लिखित याचिकाओं का निपटारा किया गया।